● वर्ष-3
● अंक-191
रायपुर, मंगलवार
19 मार्च 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› होलिका दहन पर भद्रा की छाया...

चुनाव आयोग ने 9 राज्यों के बड़े अफसरों को हटाने का दिए आदेश

नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया. वहीं आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार के भी तबादले का निर्देश दिया. साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिवों को भी हटा दिया गया है. चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद कई राज्यों में हलचल तेज हो गई है.

चुनाव आयोग की अलग-अलग प्रदेशों में हो रही इस कार्रवाई की कई वजहें बताई जा रही हैं. हालांकि निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों को समान अवसर मुहैया कराने को कारण बता रहा है.

हालांकि हर चुनाव के समय निर्वाचन आयोग कई राज्यों में जरूरत के हिसाब से तबादले करता है. इसकी कई वजहें बताई जाती हैं, जैसे अगर किसी पद पर कोई तीन साल से ज्यादा समय से बना हुआ है, या कोई अपने गृह जिले में पदस्थापित है, या कोई अधिकारी जो दो बड़ा पद संभाल रहे हो, या किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप हो. इसके अलावा भी चुनाव के समय ऐसी कार्रवाई के कई कारण होते हैं.

सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को स्थानांतरित करने का फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि अधिकारी को पहले भी राज्य में 2016 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव प्रबंधन संबंधी ड्यूटी से हटा दिया गया था. आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को राजीव कुमार को गैर-चुनाव संबंधित कार्य पर तैनात करने के लिए कहा है.

एसबीआई 21 तक दे चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारियां देः सुको

नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी विवरण का खुलासा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे। एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है सबका खुलासा किया जाए। एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे। एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम चुनावी बॉन्ड के नंबर समेत सभी जानकारी देंगे। बैंक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई एक हलफनामा दायर कर यह भी बताएगा कि उसने कोई जानकारी नहीं छिपाई है। कोर्ट ने कहा कि एसबीआई 21 मार्च शाम पांच बजे तक सारी जानकारी उपलब्ध कराएं। इस बीच, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था और शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे खेला जा रहा है। इस दौरान तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने का विचार करने को कहा है। इस मामले में सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला शुरू हो गई है।

बिहार में भाजपा 17 तो जदयू 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव

नई दिल्ली। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे पर समझौते पर पहुंच गया। बिहार में

बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दिवंगत राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के नेतृत्व वाला लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) गुट राज्य में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सहित एनडीए के अन्य सहयोगियों को क्रमशः एक-एक सीट मिलेगी।

पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, महाराजगंज, सारण, बेगुसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम उन प्रमुख सीटों में से हैं जहां भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 5 सीटों- वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई पर चुनाव लड़ेगी। गया और काराकाट सीटों पर क्रमशः हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जदयू के खाते में वामिकी नगर, सीतामढी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालन्दा, जहानबाद और शिवहर की सीटें गई है।

लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी की सुनामी में भाजपा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और दिवंगत राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) को संयुक्त रूप से 39 सीट पर जीत मिली थी। राज्य में राजग का मत प्रतिशत 53 से अधिक था, जो विपक्षी महागठबंधन को मिले मतों से लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा था। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की कम से कम छह सीट पर जीत का अंतर एक लाख मतों से कम था और इनमें से चार सीट गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में हैं। इनमें से एक लोकसभा सीट जहानाबाद है, जहां जद (यू) के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे लेकिन जीत का अंतर मात्र 1,751 मतों का था।

महागठबंधन में फंचा है पेंच

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सहयोगियों के बीच बिहार के लिए सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में इस पर मुहर लग जाएगी। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस' (इंडिया) द्वारा आयोजित एक रैली में भाग लेने के बाद राजद नेता ने कहा कि ज्यादातर मुद्दों को सुलझा लिया गया है और केवल एक या दो सीटों पर मुद्दे बचे हैं। यादव ने बताया, दो-तीन दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। यह अंतिम चरण में है। एक-दो सीटों को लेकर कुछ मुद्दे हैं, लेकिन सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल और कुछ अन्य छोटे दल लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से मुकाबला करने के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं।

कांशीराम के साथी गांधी आजाद की बहू और सांसद संगीता हुई भाजपाई

लखनऊ। बसपा के कर्ता धर्ता कांशीराम के साथी और बसपा के संस्थापकों में एक गांधी आजाद की बहू संगीता आजाद सोमवार को भाजपा में शामिल हो गईं। आजाद बसपा के टिकट पर 2019 में लालगंज सीट सांसद चुनी गईं। उनके पति भी विधायक रह चुके हैं और सास भी जिला पंचायत अध्यक्ष थीं। इस तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में किसी भी सूरत में 75 सीटों के पार जाने के लिए एक-एक सीट पर मोहरे बिछा रही है। भाजपा के ही जौनपुर के एक बड़े नेता हैं। कहते हैं कि पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। विपक्षी दल

को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। इस बार यह सीट भी निकलनी तय है।

सूत्र का कहना है कि भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से साफ निर्देश हैं कि पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को पूरे तालमेल के साथ लड़ना है। नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि इसी गुटबाजी को रोकने के लिए पार्टी ने मुंबई के पूर्व गृहराज्य मंत्री और कांग्रेस से भाजपा में आए कृपाशंकर सिंह को प्रत्याशी बना दिया। जबकि क्षेत्र में दावेदारी पांच साल से प्रयास कर रहे दूसरे दो बड़े नामों को लेकर थी। गौरतलब है कि बाहुबली नेता के रूप में गिने जाने वाले धनंजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा खुद को सात साल की सजा और गिरफ्तारी को भी राजनीतिक षडयंत्र बताया था।

लालगंज संसदीय क्षेत्र और आजमगढ़ बसपा के नेता और पुराने कार्यकर्ता गांधी आजाद के परिवार की इज्जत करता है। आसपास के जिले में भी गांधी आजाद बसपा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। सीमा आजाद को बसपा में लाने के लिए उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक काफी समय से कोशिश कर रहे थे। गांधी आजाद 1996 से 2008 तक लगातार दो बार राज्यसभा के सदस्य थे। उनके परिवार के सदस्य को भाजपा में शामिल कराने की अहमियत बसपाई रहे बृजेश पाठक को मालूम है। इसी तरह से सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भाजपा से जोड़ने में बृजेश पाठक की भूमिका रही है। राजभर ने नोनिया समेत अन्य बिरादरी में पकड़ मजबूत करने के लिए दारा सिंह चौहान को भी भाजपा में लाने का रास्ता तैयार किया। राजभर और चौहान को राज्य सरकार में मंत्री बनाने को भी भाजपा के चुनावी रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। इसी तरह से देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड में पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा भी अब भाजपाई हो चुकी हैं।

छत्तीसगढ़ में आंधी-बारिश के साथ जमकर गिरे ओले

रायपुर, खैरागढ़/गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही. छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. राजधानी रायपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, खैरागढ़ समेत कई जिलों में आंधी-बारिश के साथ जमकर ओले भी गिरे हैं. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेंहू, सब्जी और आम की पैदावार प्रभावित होने की संभावना है. ओले से पक्षियों की भी मौत हुई है. बारिश के चलते लोगों को ?गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन बेमौसम बरसात से किसानों की दिक्कतें बढ़ गई है. जीपीएम जिले में सोमवार की दोपहर अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई. जमकर ओला भी वृष्टि हुई. दानीकुंडी, मड़वाही, धरहर, ऐंठी सहित कई गांवों में इतनी अधिक ओलावृष्टि हुई कि चारों ओर जमीन की सतह बर्फ से ढक गई है।

प्रमुख समाचार

ईडी का दावा, के कविता ने आप नेताओं को दिए 100 करोड़

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया सहित शीर्ष नेताओं के साथ साजिश के जरिए आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को कथित तौर पर 100 करोड़ का भुगतान किया। ईडी के एक बयान के अनुसार, कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति-निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आप के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची। ईडी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में के कविता को 15.03.2024 को गिरफ्तार किया है। विशेष पीएमएलए कोर्ट, नई दिल्ली ने उन्हें 23.03.2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया है। 15.03.2024 को हैदराबाद में के कविता के आवास पर भी तलाशी ली गई। तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी अधिकारियों को के कविता के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बाधित किया गया था।

उद्धव ठाकरे ने फाइनल किए 16 उम्मीदवारों के नाम!

मुंबई। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद प्रचार अभियान शुरू हो गया है। इस बीच अभी तक सभी पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची का ऐलान नहीं किया गया है। महाविकास अघाड़ी की सीट बंटवारे की दुविधा अभी तक सुलझ नहीं पाई है। लेकिन शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक, ठाकरे ग्रुप के 16 उम्मीदवार तय हो गए हैं। समझा जाता है कि चार सीटों पर नाम तय नहीं हो पाये हैं। ठाकरे समूह ने मुंबई में चार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिनमें छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव, नासिक, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग और अन्य निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इसमें दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत, दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई, छत्रपति संभीजनगर से चंद्रकांत खैरे उम्मीदवार होंगे। मुंबई में बीजेपी से लड़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने खास आदमी को उतार दिया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि उत्तरी मुंबई से विनोद घोसालकर को उम्मीदवारी देने का फैसला किया गया है।

राहुल के बयान को अशोक चव्हाण ने बताया आधारहीन

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, जिन्होंने पिछले महीने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए, ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस दावे को खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस छोड़ दी और मेरी मां के सामने रोए। चव्हाण ने कहा कि पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर रविवार रात मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। राहुल ने दावा किया कि महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और मेरी मां के सामने रोते हुए कहा, सोनिया जी, मुझे शर्म आती है कि मुझमें इस शक्ति से लड़ने की शक्ति नहीं है। मैं जेल नहीं जाना चाहता. इस तरह हजारों लोगों को धमकी दी गई है। बयान के जवाब में चव्हाण ने सोमवार को कहा कि भले ही राहुल गांधी ने नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन अगर वह मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो यह निराधार और अतार्किक है।

के पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल का इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को वरिष्ठ द्रमुक नेता के पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त करने से राज्यपाल आरएन रवि के इनकार के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। राज्यपाल ने हाल ही में वरिष्ठ द्रमुक नेता और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया, मामले में कुछ तात्कालिकता थी जिसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने राज्यपाल को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने की मांग की है। सिंघवी ने कहा कि यह वही दोषी राज्यपाल है, जिस पर पहले इस अदालत ने कार्रवाई की थी। उच्चतम न्यायालय ने (पोनमुडी की) दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कोयंबटूर में रोड शो किया

कोयंबटूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में रोड शो किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगातार मोदी, मोदी के नारे लगाए और उनके स्वागत में पारंपरिक संगीत बजाया गया। जैसे ही मोदी ने एक खुले वाहन में अपना रोड शो शुरू किया, सड़क के दोनों ओर इकट्ठा हुए लोगों ने उन पर फूलों की वर्षा की और उनके स्वागत में नारे लगाए। उनमें से कई लोगों ने उत्साहपूर्वक उनकी ओर नृत्य किया और हाथ हिलाया। यह पहली बार है जब मोदी ने यहां रोड शो किया है। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष के अन्नामलाई, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, और कोयंबटूर दक्षिण विधायक और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन मोदी के साथ थीं। कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 के कोयंबटूर सिलसिलेवार बम विस्फोट पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें 58 लोगों की जान चली गई थी। 1998 कोयंबटूर बम विस्फोट शनिवार, 14 फरवरी 1998 को भारत के तमिलनाडु के कोयंबटूर शहर में हुआ था। 12 किलोमीटर (7.5 मील) के दायरे में 11 स्थानों पर हुए 12 बम हमलों में कुल 58 लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए थे। इस्तेमाल किए गए विस्फोटक टाइमर उपकरणों द्वारा सक्रिय जिलेटिन की छड़ें पाए गए और कारों, मोटरसाइकिलों, साइकिलों, दोपहिया वाहनों के साइडबॉक्स, डेनिम और रेक्सिन बैग और फलों की गाड़ियों में छुपाए गए थे।

अमित शाह का एएनआई के साथ साक्षात्कार

सीएए भाजपा के लिए संवेदना का मुद्दा है

मोदी सरकार सभी पात्र शरणार्थियों को नागरिकता देगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को समाचार एजेंसी एएनआई पॉडकास्ट को दिए गए इंटरव्यू में भारत सरकार द्वारा हाल ही लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के तथ्यों को सामने रखा और इस अधिनियम के असली उद्देश्य को देश की जनता के साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने कई विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। **(भाग-2)**

भाजपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इनकी वेदना को समझते हैं और इसीलिए उनकी 75 वर्ष लंबी इस वेदना को चुनाव से पहले समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए नागरिकता छीनने के आरोपों पर कहा कि राजनीति करने के अनेक मंच हैं, ममता बनर्जी को अपनी राजनीति के लिए बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं का अहित नहीं करना चाहिए। श्री शाह ने ममता बनर्जी को नागरिकता संशोधन अधिनियम में नागरिकता हनन करने का प्रावधान दिखाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खौफ पैदा कर रही हैं। ममता बनर्जी हिंदू और मुसलमानों के बीच द्वेष पैदा कर अपने वोट बैंक को साधना चाहती हैं। ममता बनर्जी को सीएए का विरोध करने की बजाय घुसपैठ को रोकना चाहिए। ममता न तो घुसपैठ रोक रही हैं और न ही केन्द्र का सहयोग कर रहीं हैं। राज्य सरकार के सहयोग के बिना घुसपैठ के सही आंकड़े पता लगाना थोड़ा मुश्किल है और वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार होगी और घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ममता बनर्जी इसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तुष्टिकरण की राजनीति करेंगी तो जनता उनके साथ नहीं रहेगी। कई लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के कारण शायद आवेदन करने से भी डरेंगे परन्तु उन्होंने सभी शरणार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी शरणार्थी अपना आवेदन करें, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव से सबको नागरिकता देगी।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने या नहीं होने के संशय पर कहा कि असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं इसका नागरिकता संशोधन अधिनियम से कोई

लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ असम ही ही नहीं देश के हर हिस्से में यह कानून लागू होगा। सिर्फ उत्तरपूर्वी राज्य जिन्हें 2 प्रकार के विशेषाधिकार दिए गए हैं उसके तहत सिर्फ उन्ही राज्यों में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। इन 2 विशेषाधिकारों में इनर लाइन पर्मिट का प्रावधान है और दूसरा संविधान की अनुसूची 6 में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। श्री शाह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में उनकी रचना और उनके अधिकार को बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा। अधिनियम के तहत ही प्रावधान किया गया है कि जहां पर भी इनर लाइन पर्मिट है और संविधान की अनुसूची 6 में जो क्षेत्र शामिल किये गए हैं वहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा एवं वहाँ का पता वाला भाग भी मोबाईल ऐप्लकैशन में अपलोड नहीं होगा।

केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं किए जाने के मुद्दे पर श्री शाह ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद को दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। इसलिए नागरिकता के बारे में कानून और उसे लागू करना दोनों ही भारतीय संविधान के 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसे अनुसूची 7 में डाला गया है और इसकी तमाम शक्तियां भी केंद्र को दी गई हैं। कोई भी नागरिक छूटेगा नहीं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सीएए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया और लागू किया गया है। इंडी गठबंधन के नेता जो सरकार बनने पर कानून रद्द करने की बात कर रहे थे, वे आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। जो नेता अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं वे इसके दो अपवादों को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें उचित वर्गीकरण और प्रावधानों और उद्देश्यों के बीच एक तार्किक संबंध शामिल हैं।

(क्रमश)...

जनजातियों के गांव तक सुरक्षा के साये में पहुंची सड़क

■ 15 साल में 24 बार हो चुका था टेंडर

गरियाबंद। जिले में सबसे सुदूर कहे जाने वाले आमामोरा ओड इलाके में अब नेशनल हाइवे से महज 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अब यहां पथरीला, टेढ़ी-मेढ़ी सड़क नहीं बल्कि पक्की सीसी और चमचमाती डामर वाली सड़क बनने जा रही है। धवलपुर नेशनल हाइवे से कुकुरार तक 31।65 किमी सड़क बनना शुरू हो गया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग ने 20 करोड़ लागत से बनने जा रही सड़क को पांच अलग-अलग टेंडर जारी कर काम शुरू कर दिया है। अब तक 10 किमी का निर्माण पुरा हो चुका है। जिसमें पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई वाला हिस्सा कहे जाने वाले चिखली पठार से ओड़ तक बन रहे 6।5 किमी में से लगभग 5 किमी की सड़क सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण पुरा कर लिया गया है। शेष भाग में मुरम मिट्टी का काम हो चुका है जिससे पहले की अपेक्षा आवाजाही बड़ी आसानी से हो पा रही है।विभाग के ईई बीआर सोनी ने कहा कि अब तक 10 किमी मार्ग बन चुका है। काम तेज गति से जारी है। कुछ जगह वन विभाग की आपत्ति थी जिसके निराकरण के लिए पत्राचार हो गया। निर्माण कार्य जून जुलाई तक पुरा करा लिया जाएगा।

सड़क का पुरा निर्माण कार्य सीआरपीएफ बटालियन 65 के निगेहबानी में हो रहा है।साल भर पहले ही छिंदौला और ओड़ में सीआरपीएफ कैंप की स्थापना की गई,जिसके बाद बटालियन अपनी मौजूदगी में निर्माण कार्य करवा रही है। एसपी अमित तुकाराम कांबले के निर्देशन में डीआरजी भी सीआरपीएफ के साथ समन्वय कर ज्वाइंट ऑपरेशन चला कर उस इलाके से नक्सलियों को खदेड़ने में सफल हुई है।अपको बता दे में जनजाति

के लिहाज से इस क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है।2007 में ही भाजपा सरकार ने निर्माण के लिए 9।6 करोड़ की मंजूरी दे दिया था।टेंडर की प्रक्रिया चल रहा था इसी बीच 2009 में नक्सल को धमक हुई।2011 में इसी इलाके में नक्सली एंबूस में एएसपी समेत 10 जवान शहीद हो गए थे।लगातार नक्सली अपनी उपस्थिति देते रहे 2015 में भी बम फटने से दो जवान शहीद हो गए थे।सड़क के लिए 2021 तक 24 बार टेंडर जारी किया जा चुका था।लेकिन हाई लेबल बैठक के बाद 2022 में सुरक्षा बल तैनात करने के निर्णय ने सड़क निर्माण की राह आसान कर दिया।अब सड़क मूर्त रूप ले रहा है,जिसे ग्रामीण विकास लाने वाली सड़क मान रहे हैं। आमामोरा पंचायत के अधीन कूकरारा, नगरार व ओड़ में अमलोर,हथौड़ा डीह मिलाकर कूल 7 गांव में 350 परिवार में 1500 लोग रहते हैं,जिन्हे सड़क के अभाव में कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता था।सड़क बनते ही कैसे बदलाव आयेगा ऐसे समझें

क्षेत्र के लिए उपस्वास्थ्य केंद्र तो है पर पृथक भवन नही,इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियो के रहने के लिए आवास नहीं होने के कारण उन्हें 30 किमी नीचे धवलपुर में रहना पड़ता था।

7 गांव के लिए दो आश्रम शाला है। जहां मिडिल स्कूल तक की पढ़ाई हो पाती है। प्रति वर्ष 9 वी पढ़ने लायक 12 से15 बच्चे पास होते हैं। वार्ड 9 के पंच लखन यादव,भगवान यादव समेत क्षेत्र के जागरूक लोग बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने बताया कि मार्ग सुगम नहीं होने के कारण 3,4 बच्चे नीचे पढ़ने जा पाते हैं।ऊपर में हाई स्कूल की मांग पर भी विचार नहीं हो रहा था।सड़क बनते ही दोनों ओर सहूलियत होगी।

ओड़ के सरपंच रामसिंह कमार जनजाति से हैं। उन्होंने अपनी व्यथा बताया कि अन्य पंचायत की तरह यहां विकास कार्य बहुत कम है, वजह पहुंच विहीन होने के कारण। इलाका वन क्षेत्र होने के कारण मनरेगा से सीमित काम होता है। इसलिए हर साल हथौड़ाडीह और अन्य क्षेत्र से 100 से ज्यादा कुमार मजदूर ईट भट्ठे में काम करने आंध्र पलायन कर जाते हैं। उनके साथ पढ़ाई करने वाले आश्रम के बच्चे भी भाग जाते है।अब तस्वीर बदलने की उम्मीद है।

सड़क जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सड़क किनारे बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। आवाजाही में दिक्कतों के कारण बिजली उपक्रम ऊपर के गांव में नही पहुंच पा रहा था। अब बिजली लगाने की भी तैयारी प्रशासन कर रही है।

यह इलाका ऊंचाई पर होने के कारण यहां का तापमान गर्मी के दिनों मे भी समान्य रहता है। शीत ऋतु में बर्फ के चादर यहां देखने को मिलता है। दो सुंदर झरने भी यहां मौजूद है जिसे उदंतीसीता नदी अभ्यारण्य बढ़ावा देती है। निर्माणाधीन सड़क से आवाजाही होना शुरू हुआ तब से इस इलाके में विदेशी पर्यटक आना शुरू कर दिया था। कार्य पूर्ण होने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा,जिससे स्थानियय वन समितियों के आय में वृद्धि होगी।

खनिज न्यास में भारी गड़बड़ी, फेकल्टी मेंबर की सेवा समाप्ति के खिलाफ याचिका

■ सीईओ को नोटिस जारी कर किया तलब

बिलासपुर। जांजगीर-चांपा में जिला खनिज न्यास मद में 52 लाख रुपये की गड़बड़ी हुई, यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में जिला पंचायत ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाए एक फेकल्टी मेंबर की सेवा समाप्त कर दी। उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब नहीं देने से नाराज हाईकोर्ट ने सीईओ को घोटाले की फाइल के साथ 9 अप्रैल को तलब किया है।

इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता चंद्रहास जायसवाल ने एडवोकेट प्रतीक शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिसमे बताया गया है, कि जिला पंचायत जांजगीर-चांपा में मुख्यमंत्री सशक्तीकरण योजना के तहत संकाय सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जिस पर याचिकाकर्ता को मैरिट लिस्ट के आधार पर 25 जनवरी 2017 को नियुक्ति दी गई। इस बीच बिना किसी शिकायत के वह 9 सितंबर 2023 तक काम करता रहा।

याचिकाकर्ता के मुताबिक जिला खनिज संस्थान न्यास मद के अंतर्गत कौशल विकास और रोजगार चयन में मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण सह टूल्स प्रदाय व अन्य कार्य के लिए 30 मार्च 2021 को 52 लाख 4 हजार 500 रुपए की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति मिली। इसके लिए विधिवत टेंडर मंगवा कर काम कराने के बाद भुगतान किया गया। जिसके बाद डीएमएफ के इस काम में गड़बड़ी की शिकायत की

गई, तो जांच में 52 लाख रुपए की गड़बड़ी पाई गई, और कलेक्टर के निर्देश पर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई।

याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस काम के लिए उन्हें दोषी बताया गया है, उसमें उनका काम केवल विभाग में प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करना था, लेकिन उन पर ही कार्रवाई की गई, राशि के लेनदेन में शामिल किसी अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास के सिंगल बेंच में चल रही है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले में जिला पंचायत सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और उन्हें उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, तो जस्टिस व्यास ने नाराजगी जाहिर करते हुए सीईओ को घोटाले की फाइल सहित सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी।

बलरामपुर में इको फ्रेंडली रंग बना रही महिलाएं

बलरामपुर। रंगों का त्यौहार होली अब नजदीक आ चुका है। इस साल 25 मार्च को होली का त्योहार मनाया जा रहा है। आजकल लोग होली पर हर्बल गुलाल और रंगों से ज्यादा खेलना पसंद कर रहे हैं। लोगों की इस डिमांड को देखते हुए बलरामपुर स्वसहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही है। इससे महिलाओं की आजीविका में बढ़ोतरी तो हो ही रही है, लोगों को भी कम कीमत पर हर्बल रंग मिल रहे हैं।

बलरामपुर के ग्राम पंचायत भनौरा में गंगा महिला स्व सहायता समूह हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कई गांवों की महिलाओं को इस ग्रुप से जोड़ा गया है। इस समूह में कई महिलाएं पिछले 3 साल से जुड़ी है। जो तीज त्योहारों पर अलग अलग चीजें बनाकर मार्केट में उन्हें बेचकर पैसे कमाती हैं। इस समय होली के त्योहार को देखते हुए महिलाएं इको फ्रेंडली रंग बना रही है। पलाश के फूल, चुकंदर, लालभाजी, हरी भाजी, हल्दी और चंदन, अरारोट पाउडर को मिला कर ये रंग बनाए जा रहे हैं। पूरी तरह से प्राकृतिक होने के कारण इन रंगों से होली खेलने से त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता।

खाने की इन चीजों से बनते हैं प्राकृतिक रंग

लाल रंग- लालभाजी, गुलाबी रंग- चुकंदर, हरा रंग- कोई भी हरी भाजी, पीला- हल्दी, संतरा- पलाश के फूल।

पिछले तीन साल से समूह की महिलाएं रंग

गुलाल तैयार कर रही हैं। पिछले साल लगभग चार क्विंटल रंग गुलाल की बिक्री हुई थी। मार्केट में हर्बल रंगों की डिमांड को देखते हुए महिलाएं इस बार भारी मात्रा में रंग गुलाल तैयार करने में जुटी हुई हैं।रंगों की कीमत 20 रुपये से लेकर 150 रुपये तक रखी गई है। सदस्य स्वयं सहायता समूह सविता कुमारी ने कहा हम प्राकृतिक चीजों से गुलाल बना रहे हैं। फूल पत्तियों से रंग तैयार करते हैं। जिसे अरारोट में मिलाकर, लाल, नीला, पीला, गुलाबी, हरा रंग तैयार कर रहे हैं। गंगा महिला स्व सहायता समूह सदस्य रेखा सिंह ने कहा पिछले तीन सालों से हर्बल गुलाल बना रहे हैं। पलाश के फूल और सब्जियों से रंग बनाते हैं। इससे त्वचा और शरीर के दूसरे अंगों को कोई नुकसान नहीं होता।

बलरामपुर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है। हर्बल रंग गुलाल को कलेक्ट्रेट, जनपद कार्यालय और अलग अलग सरकारी विभागों के माध्यम से स्टॉल लगाकर और सी- मार्ट के जरिए बिक्री किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ का एक अनोखा गांव जहां हफ्तेभर पहले ही मना ली गई होली

■ तिथि पर त्योहार मनाने से होती है अनहोनी

धमतरी। वैसे तो रंगों का त्योहार होली आने वाले 25 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन अपने अनोखे दस्तूर के चलते धमतरी के एक गांव के लोग सोमवार को ही होली मना लिए। हफ्तेभर पहले ही त्योहार मनाने सदियों की इस परम्परा को मौजूदा पीढ़ियां भी आगे बढ़ा रही है। अब वो चाहे दिवाली हो या फिर पोला।

बताया जाता है कि इस लकिर को तोड़ने की जुर्रत करने पर कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। इसके कारण दिगर जगहों से अलग त्योहार मनाने का ये तरिका अब इस गांव की पहचान बन चूकी है, जिसे देखने हर मौके पर लोग दूर-दूर से आते हैं।

वक्त जरूर बदला लेकिन धमतरी के सेमरा (बी) गांव का दस्तूर आज भी कायम है। यहां होली आज मनाई गई है। धमतरी से करीब 22 किमी दूर इस गांव में हफ्तेभर पहले ही त्योहार मनाने का अनोखा दस्तूर है। अब वो चाहे दिवाली का हो या फिर अन्य त्योहार। इस दस्तूर के अतीत में एक दास्तान छिपी है। सदियों पहले गांव के देवता सिरदार ने सपने में कहा था कि हर त्योहार मनाने के पहले उन्हें हुम धूप देना

जरूरी है। इसके चलते आज भी गांव के लोग अपने गांव के देवता को खूश करने हर त्योहार हफ्तेभर पहले मनाते आ रहे हैं, जो अब एक परम्परा बन गई है।

भले ही आज के जमाने के लोग इस पर यकिन ना करें, लेकिन बताया जाता है कि ऐसा नहीं करने से उनके ऊपर आफत आ सकती है। सदियों से चली आ रही इस परम्परा को युवा वर्ग भी अंधविश्वास के बजाए आस्था से जोड़कर देखता है और इसे आगे संजोए रखने का यकिन दिलाती है। उनकी माने तो इसी दस्तूर के बहाने उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने और मेहमाननवाजी का मौका मिल जाता है, जो यहां त्योहार देखने आते हैं।

फर्जी वोटर्स के खिलाफ एफआईआर कर पोस्टर लगाने वालों को पुलिस देगी इनाम

कवर्धा। कबीरधाम पुलिस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस हर क्षेत्र से फर्जी वोटर्स का पता कर रही है। लोहारा ब्लॉक में पुलिस को ऐसे ही फर्जी वोटर्स के बारे में पता चला है जिनके बारे में जानकारी देने वालों को पुलिस ने इनाम देने की घोषणा की है।

फर्जी वोटर्स पर कवर्धा पुलिस सख्त- कवर्धा में पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है। जब पुलिस ने फर्जी वोटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर इनाम देने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीणों की शिकायत पर लोहारा पुलिस ने 5 फर्जी वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिया है। सभी फर्जी वोटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। गांव-गांव में पांटों फर्जी वोटर्स के पोस्टर चिपकाए गए हैं। पुलिस ने इनके बारे में जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है।

लोहारा थाना प्रभारी ने कहा लोहारा ब्लॉक के ग्राम बचेड़ी में वोटर्स लिस्ट में पांच ऐसे नाम हैं जिनका गांव से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही इन लोगों को गांव का कोई जानता है। इन व्यक्तियों का पोस्टर गांव-गांव में लगाकर इनके बारे में जानकारी देने वाले को इनाम की घोषणा की गई है।

ये हैं फर्जी वोटर्स- फर्जी वोटर्स मोहम्मद जहीर, रशीद चौहान, हाजी बुल्ला खान, सैय्यद खान, अब्दुल सलाम है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब पुलिस ने मामले की जांच की तो इन फर्जी वोटर्स का खुलासा हुआ। इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

संत बाबा गुरु घासीदास जी मेमोरियल अस्पताल में उगाही

रायगढ़। अस्पताल मरीजों की मदद और उनके इलाज के लिए है। लेकिन जब यहां के कर्मी ही मरीजों के साथ जबरन लूट खसोट मचाने लगे तो क्या होगा। रायगढ़ के संत बाबा गुरु घासीदास जी मेमोरियल अस्पताल में मरीजों ने यहां के सुरक्षा गार्ड पर जबरन वसूली का आरोप लगा दिया। जांच के बाद इस केस में तीन गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक एक गर्भवती महिला की भर्ती के दौरान कथित तौर पर महिला के रिश्तेदारों से अस्पताल में एडमिट के लिए सुरक्षा गार्ड ने पैसे लिए। यह घटना रविवार की है। रायगढ़ पुलिस के अधिकारी ने कहा रविवार को यहां संत बाबा गुरु घासीदास जी मेमोरियल सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए एक महिला आई थी। यहां महिला मरीज के रिश्तेदारों को प्रवेश पास जारी करने के लिए कथित तौर पर प्रति व्यक्ति 100 रुपये की मांग की गई। कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने अस्पताल प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अग्निवीर थल सेना भर्ती की अंतिम तिथि 22 मार्च तक

बलरामपुर। अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना 13 फरवरी 2024 को जारी कर दी गई थी। इस भर्ती मे आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2024 निर्धारित है। इस भर्ती के तहत् अब तक लगभग 160 उम्मीदवारो ने अपना आवेदन पंजीयन किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 मार्च तक निर्धारित समय में अग्निवीर की वेबसाईट ''ज्वाईन इंडियन आर्मी'' पर अपना पंजीयन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी या समस्या के लिए सेना भर्ती कार्यालय शहीद वीर नारायण सिहं अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परसदा, रायपुर में स्वयं उपस्थित होकर या कार्यालय के टेलीफोन नम्बर 0771-2965212/0771-2965213 पर संम्पर्क कर सकते है।

हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, यातायात बाधित

कोरबा। कोरबा जिले में लगातार हादसों का दौर जारी है एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। सर्वमंगला चौकी के तहत कनकी कनबेरी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई वहीं ग्रामीण भी काफी संख्या में मौजूद रहे। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया जिससे लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज रही थी जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। किसी तरह पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कर शव को जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया। कुसमुंडा थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों को समझाइस दी गई है इसके लिए एसईसीएल और जिला प्रशासन से बात हुई है जहां ग्रामीणों की मांग पर अमल किया जाएगा। फिलहाल इस घटना में मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।

चेकिंग के दौरान एफएसटी ने जब्त किया लाखों रुपये कैश

जांजगीर चांपा। वाहन चेकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने 7 लाख 95 हजार रुपये जब्त किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एफएसटी एसएसटी की टीम गठित की गई है। जो लगातार कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक खोखरा गांव का रहने वाला अमित कुमार थवाईत कार में कैश लेकर जा रहा था। कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर टीम ने नगद जब्त कर लिया। जिसके बाद कैश जीएसटी विभाग को भेजा दिया गया है। ये कार्रवाई बनारी में की गई है।

तुमड़ीबोड़ पुलिस फायरिंग रेंज में विस्फोटक से बच्चा घायल

राजनांदगांव। तुमड़ीबोड़ चौकी क्षेत्र के तिलईरवार गांव के पास पुलिस का फायरिंग रेंज बना हुआ है। रविवार को एक बच्चा अपने साथियों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गया। इस दौरान बच्चे ने एक विस्फोटक को अपने हाथ में उठा लिया। जिससे विस्फोटक बच्चे की हाथ में फट गया और बच्चा घायल हो गया। बच्चे के घायल होने की सूचना गांव वालों को लगी। घरवालों तक बात पहुंची। जिसके बाद माता पिता और गांव वाले तुरंत बच्चे को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। बच्चे के पिता के मुताबिक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे जिसके बाद बच्चे को लेकर निजी अस्पताल लेकर गए। जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। बच्चे के पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस जगह पर फायरिंग रेंज बनी हुई है वह सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। बच्चे का पिता ने कहा फायरिंग रेंज वालों की गलती है। बाउंड्री भी नहीं है, तार का घेरा भी नहीं है।

शिवपुर चरचा की नपा अध्यक्ष लालमुनि का भाजपा विधायक पर बड़ा आरोप

कोरिया। जिले की शिवपुर चरचा की नगरपालिका अध्यक्ष ने बैकुंठपुर विधायक पर कई आरोप लगाए। नगरपालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव का कहना है कि विधायक भैयालाल राजवाड़े कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लालमुनि ने खुदपर भी दबाव बनाने का आरोप विधायक पर लगाया।

कहां से शुरू हुआ विवाद

नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अपर सचिव ने कोरिया जिले की नगर पालिका शिवपुर चरचा की अध्यक्ष लालमुनि यादव के वित्तीय अधिकार को निलंबित करने का आदेश जारी किया। इसके बाद लालमुनि यादव ने बीजेपी विधायक भैया लाल राजवाड़े पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक उनके पार्षदों को अपने खेमे में

लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कई तरह से दबाव बनाया जा रहा है। यादव ने कहा की चरचा के विकास कार्यों को लेकर भाजपा विधायक ने सीएमओ को आदेश दिया है कि किसी भी कार्यों का चेक नहीं काटे, इस वजह से क्षेत्र के कई विकास कार्य रुक गए हैं।

लालमुनि यादव, शिवपुर चरचा अध्यक्ष ने कहा राजनीतिक षड़यंत्र है। पहले हमारे पार्षदों को तोड़ने की कोशिश हुई, जब पार्षद नहीं टूटे तो हम पर दबाव बनाया गया। ये पूरा विधायक भैया लाल राजवाड़े का खेल है। हमारे यहां सभी काम रोक दिए गए हैं। राजवाड़े सीएमओ पर दबाव बना रहे थे कि किसी भी चैक पर साइन ना करें।

विधायक ने आरोपों को किया खारिज

नगरपालिका अध्यक्ष के आरोपों को विधायक ने खारिज कर दिया। बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि- भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 18 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य भाजपा में है। कांग्रेस का अस्तित्व ही क्या है कि हम कांग्रेस पार्षदों को भाजपा में शामिल होने को कहेंगे। झूठा आरोप लगाया जा रहा है। बिना टेंडर और बिना स्वीकृति के काम और चैक काटकर पैसा निकाला जा रहा है। जांच के बाद आरोप सही पाए गए इस वजह से अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार को निलंबित किया गया है।

विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा शिवपुर चरचा की नगरपालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव मनमानी कर रही है। इनकी रिपोर्ट पूरे पार्षदों ने उच्च अधिकारियों की दी, जिसके बाद जांच की गई। उस आधार पर कार्रवाई की गई है। रेलवे की जमीन पर बिना परमिशन के टाइल्स और बैंच लगाया गया है। ये सब कैसे हुआ।

भैयालाल राजवाड़े ने लालमुनि यादव के खिलाफ आगे भी जांच प्रक्रिया जारी रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी मनमानी रोकने के लिए पार्षदों ने ही शिकायत की थी। ये उनके कामों का परिणाम है। आगे भी जांच चलती रहेगी।

प्रोफेसर को जान से मारने की धमकी

■ पहले फोन कर मिलने बुलाया, फिर पास न करने पर किया गाली गलौच, दो गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के तहत ओरिएंटल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर पदस्थ एसईसीएल सुभाष ब्लॉक निवासी महेश्वर भारती को कुछ युवकों ने फोन किया और एडमिशन लेने संबंधित बातचीत की। प्रोफेसर ने कॉलेज जाकर इस संबंध में जानकारी लेने की बात की लेकिन उसके बाद भी युवक फोन करके परेशान कर रहे थे तब प्रोफेसर ने तंग आकर युवकों से मुलाकात की।

प्रोफेसर अपने पत्नी और बच्चों के साथ कार पर गया इस दौरान युवक उनसे मिले और सीधे गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। जब प्रोफेसर की पत्नी कार से नीचे उतर कर मोबाइल में वीडियो बनाने लगी तो सभी मौके से फरार हो गये। प्रोफेसर ने इसकी शिकायत मानिकपुर चौकी पुलिस से की जहां पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर

दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

प्रोफेसर ने बताया कि ओरिएंटल मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी एक प्रोफेसर को धमकी दी जा चुकी है। इस घटना के बाद से वह डरा सहमा हुआ है। इसलिए उसने तत्काल पुलिस से शिकायत की है।

मानिकपुर चौकी प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि प्रोफेसर ने एक लिखित शिकायत की थी जिसमें बताया कि, कुछ युवकों के द्वारा पेपर में पास करने को लेकर धमकी दी जा रही है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

संक्षिप्त समाचार

गेट एग्जाम में रायपुर के सिद्धेश ने ऑल इंडिया लेवल पर 33वां रैंक किया हासिल

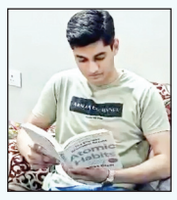

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रहने वाले सिद्धेश पांडेय ने आईआईटी में दाखिले के लिए कराई जाने वाली परीक्षा गेट (ग्रेजुएट एप्टीटयूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) 2024 में देशभर में 33वां स्थान हासिल किया है। कमल विहार के रहने वाले सिद्देश आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। इसके अलावा वह छुश्वश्व 2019 के टॉपर्स में भी शामिल थे। सिद्धेश के पिता प्रशांत पांडेय एलआईसी में कार्यरत हैं जबकि मां डॉ। स्वाति पांडेय होम मेकर हैं। मीडिया से हुई बातचीत के दौरान सिद्धेश ने बताया कि वह किसी भी काम को करने से पहले उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेते है। जब वह 10वीं में थे तब उन्होंने यह निश्चय कर लिया था की वह छुश्वश्व क्रैक करेंगे। इसके बाद जब वह 12वीं में थे तब उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने की ठानी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया। इस दौरान पहले सेमेस्टर में ही सिद्धेश ने यह तय कर लिया था कि उन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाना है। ग्रेजुएट के बाद उन्होंने लगातार मेहनत की और गेट की परीक्षा में देशभर में 33वां स्थान हासिल किया। सिद्धेश ने बताया कि उनकी रैंकिंग के अनुसार किसी भी महारत्न पीएसयू में जॉब की संभावना अधिक है।

31 मार्च को खुले रहेंगे राज्य के सभी कोषालय व उपकोषालय

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर का हैं कि को आर.बी.आई. के ई-कुबेर प्रणाली को कार्य दिवस अंकित किया गया है। 28 मार्च 2024 तक कोषालयों में लगाये जाने वाले देयकों को पारित करने एवं शासकीय जमा संबंधी वित्तीय संव्यवहारों के निष्पादन के लिए 31 मार्च को समस्त कोषालयों/ उपकोषालय खुले रहेंगे। उक्त आदेश विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के निखिल कुमार अग्रवाल के हस्ताक्षर से जारी हुआ।

राजनांदगांव के चिखली में विदेशी मदिरा दुकान विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

राजनांदगांव। चिखली में खुलने जा रहे नए

विदेशी मदिरा दुकान के खिलाफ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कांग्रेसी पार्षदों और वार्डवासी राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि चिखली में खुलने वाले शराब दुकान के निविदा को निरस्त किया जाए। जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड राजनांदगांव ने एक निविदा जारी किया है। जिसके मुताबिक, वार्ड नंबर 22 में संचालित विदेशी मदिरा दुकान को चिखली वार्ड नंबर 6 में संचालित करने आदेश दिया गया है, जिसका वार्डवासी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। सोमवार को चिखली के वार्डवासी, कांग्रेसी पार्षद और महापौर समेत कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जहां सभी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि प्रशासन चिखली में विदेशी मदिरा दुकान संचालित करने निविदा को निरस्त कर किसी अन्य जगह पर संचालित करने निविदा जारी करे। शराब दुकान के संचालन से चिखली वार्ड वासियों की परेशानी बढ़ जाएगा। अगर चिखली में शराब दुकान संचालित करने पर वार्डवासियों ने उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। महापौर हेमा देशमुख ने कहा हमने कलेक्टर साहब से आपत्ति दर्ज कराई है कि चिखली में जो शराब दुकान खोलने की बात आ रही है, उससे पूरे वार्ड वासियों को आपत्ति है। इस नई जगह पर शराब दुकान खोलने का विरोध वार्डवासी सहित कांग्रेस पार्षद विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में कलेक्टर को पत्र सौंपा गया है।

अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए भूपेश : बृजमोहन अग्रवाल

महादेव बेटिंग एप को लेकर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस

रायपुर। महादेव बेटिंग एप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा भूपेश बघेल और कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है। इस संबंध में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर और मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि महादेव बेटिंग एप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बयानबाजी की है, भाजपा और सरकार पर जो आरोप लगाया है वो निराधार और बेबुनियाद है।

उनका आरोप लगाना वैसा ही है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहे हैं। उन्हें न्यायालयीन और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। एक तरफ वे दावा करते हैं कि महादेव बैटिंग एप मामले में जांच की कार्रवाई हमने शुरू की और उसी जांच के क्रम में जब एफआईआर दर्ज होती है तब वे बौखला जाते हैं। पेट में दर्द होने लगता है। आगे उन्होंने कहा कि ना तो चुनाव से एफआईआर का कोई लेना देना है, ना राजनीतिक विद्वेशवश एफआईआर किया गया है। केवल जांच प्रक्रिया के क्रम में एफआईआर दर्ज हुई है। यह जांच की सतत प्रक्रिया का हिस्सा है।

आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि आज देश का मूड स्पष्ट रूप से दिखता है। अबकी बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। भाजपा को किसी विद्वेष में काम करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व सीएम की गिरफ्तारी को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि कानून अपना काम करेगा।

गिरफ्तार आरोपी और अधिकारियों से उनके क्या संबंध हैं- बृजमोहन

वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि चोरी ऊपर से सीना जोरी के तर्ज पर भूपेश बघेल रायपुर से भाग कर राजनांदगांव गए। महादेव सट्टा एप के नाम पर पहले एफआईआर उन्होंने ही दर्ज कराया था। अपने ही बुने हुए जाल में वह खुद फंस गए हैं। गिरफ्तार आरोपी और अधिकारियों से उनके क्या संबंध है उन्हें बताना चाहिए। इतने सारे घोटाले किए, अभी तो एक ही घोटाले में उनका नाम आया है। असीम दास के बयान को वो सही मानते हैं या नहीं।।? शुभम सोनी के वीडियो जो सामने आए थे उसके बारे में भूपेश बघेल का क्या कहना है? आज तक कोई तथ्यात्मक बयान नहीं आया है।

बृजमोहन ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के 10 लाख युवाओं को महादेव एप सट्टे में उलझाकर रखने की दोषी कांग्रेस और भूपेश बघेल है। इनके लोगों की जमानत याचिका खारिज हुई है। क्या इनको न्याय पालिका पर विश्वास नहीं है ? ईडी, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई पर विश्वास नहीं है क्या ? राजनीतिक मुकदमे दर्ज करने का इतिहास बीजेपी का नहीं है। ये उनका इतिहास है। बीजेपी को सरकार को इन सब कामों की फुरसत नहीं है। हम मोदी की गारंटी पर काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल को जांच में सहयोग करना चाहिए ना कि धमकी और जांच से भागना चाहिए।

भूपेश के समय में ही जांच शुरू हुई थी : केदार

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा एप को लेकर हुई एफआईआर को लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के समय में ही मामले की जांच शुरू हुई थी। कानूनी मामला है जो सत्य है वो बाहर आए। यदि दोष हो तो उन पर कार्रवाई हो। आज भी महादेव एप को लेकर गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें उनका नाम स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यदि वो दोष मुक्त हैं तो उनको कानूनी तरीके से बात करनी चाहिए। ये बिलकुल राजनीतिक एफआईआर नहीं है। बीजेपी इस तरह से कोई कृत्य नहीं करती है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई में हेरफेर हुआ है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते अपनी सत्यता जनता के सामने लानी चाहिए।

पहले चरण में बस्तर लोकसभा के होने वाले चुनाव को लेकर केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर में 20 तारीख से मुख्यमंत्री का प्रवास शुरू होगा जो होली तक चलेगा। सभी विधानसभा में जाने की तारीख तय हो रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री सहित पार्टी के बड़े नेताओं के आने की भी संभावना है। पिछली बार कांग्रेस धोखे से बस्तर लोकसभा जीती थी। लेकिन इस बार वहां के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। विधानसभा में जो आशीर्वाद बस्तर में मिला ठीक वैसा ही आशीर्वाद लोकसभा में भी मिलेगा।

बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला है

कांग्रेस नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक और पूर्व विधायक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। लगातार उनके परिवार में गुटबाजी बढ़ रही है। वो चाहते हैं अच्छे नेता और पार्टी के संपर्क में आएं। डूबती हुई नैया में कोई भी नहीं चढ़ना चाहता। इसलिए वहां से सब छोड़कर जा रहे हैं। जो भी बीजेपी में आना चाहता है पार्टी का दरवाजा हमेशा खुला है सबका स्वागत है।

कांग्रेस ढूंढ रही है कि बलि का बकरा किसे बनाएं

कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है इसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी बार सर्वे कराएगी। 400 से ज़्यादा सीट बीजेपी की आएगी। मुझे लगता है कांग्रेस के पास राज्यसभा सांसद के लिए नेता नहीं थे। उसी तरह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई नेता नहीं होगा। इसलिए नाम ढूंढ़ रहे हैं कि बलि का बकरा किसे बनाया जाए।

आदिवासी विरोध में खड़ा हुआ तो उसे जेल भेज देंगे : कांग्रेस

सावधान बस्तर : यह सब बेच डालेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सियासी पारा गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस-भाजपा के बीच पोस्टरवार शुरू हो गया है। भाजपा के बाद कांग्रेस ने एक के बाद एक कई पोस्टर जारी कर भाजपा पर निशाना साधा है। पोस्टर के जरिए भाजपा और कई भाजपा नेताओं पर हमला बोला है।

बता दें कि कांग्रेस ने लगातार 3 पोस्टर जारी किए हैं, जिसमें एक पोस्टर अडानी और मोदी का है। दूसरा गौसेवक साधराम हत्या मामले में गृहमंत्री विजय शर्मा का और तीसरा पोस्टर लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडेय का। जिन पर पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने हमला बोला है।

पहले पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने मोदी और अडानी पर हमला बोलते हुए कहा, सावधान बस्तर- धरा बेच देंगे , गगन बेच

देंगे कली बेच देंगे ,सुमन बेच देंगे जागो भारतवासी, सत्ता के पुजारी वतन बेच देंगे।

वहीं दूसरे पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने गृहमंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए लिखा, गौ सेवक साधराम की हत्या हुई तो भाजपा के नेता इसलिए मौन थे क्योंकि उस समय कोई चुनाव नहीं था। तीसरे पोस्टर के जरिए कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडेय पर कांग्रेस ने हमला करते हुए लिखा, कोरबावासी सावधान- पिकनिक मनाने सैलानी आए हैं। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे।

महादेव बेटिंग एप से छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटा : साव

लुटेरों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आरोपों को लेकर पलटवार किया। अरुण साव ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कानून का सम्मान नहीं कर रहे इसलिए घूमघूम कर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर रहे हैं।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने सोमवार को संभागीय भाजपा कार्यालय बिलासपुर में प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में काले धन का उपयोग रुकना चाहिए। इसके लिए ठोस और मजबूत कार्रवाई करना जरूरी है। इसी के तहत पूर्व सीएम पर कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉरलेंस की नीति के तहत पूर्व सीएम पर एक्शन लिया गया है। कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस शासनकाल में छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिए थे। प्रदेश का पैसा लूट कर कांग्रेस के बड़े नेताओं को पहुंचा रहे थे। महादेव सट्टा एप, शराब घोटाला, कोल स्कैम जैसे कई बड़े घोटाले छत्तीसगढ़ में हुए हैं। अब ईडी उन पर कार्रवाई कर रही है तो

उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा महादेव सट्टा ऐप मामले में जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। राजनीति या चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। महादेव सट्टा एप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है।

बयानबाजी से बचें पूर्व सीएम

साव ने आगे कहा कि असीम से 500 करोड़ से ज्यादा की राशि बरामद की गई। उसने अपने बयान में कहा कि यह पैसा भूपेश बघेल को दिया जाना था और यही वजह है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन भूपेश बघेल खुद को साफ सुथरा बताकर कानून की कार्रवाई का का सम्मान नहीं कर रहे हैं। भूपेश बघेल बिना तथ्य आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूर्व सीएम को चाहिए कि वह कानून का सम्मान करें और अनाप शनाप बयानबाजी से खुद को बचाएं।

चुनाव के ऐलान के बाद समझिए प्रदेश का एसडब्ल्यूओटी फैक्टर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी कांग्रेस की मजबूती और कमजोरी को ध्यान में रखकर अगर सोचा जाए तो कैसी तस्वीर होगी। यह सोचने वाली बात है। इसके लिए SWOT विश्लेषण किया गया है, जिसे (SWOT= Strengths मजबूती, Weaknesses कमजोरी, Opportunities अवसर और Threats परेशानी या चिंता में बांटा गया है।)

भाजपा का SWOT फैक्टर समझिए

बीजेपी के SWOT फैक्टर पर नजर डाले तो पीएम मोदी की लोकप्रियता उसका ट्रंप कार्ड है। जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। साल 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंपर जीत दर्ज की थी। लेकिन मोदी की लोकप्रियता के सामने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस धराशाई हो गई और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। इसके अलावा महतारी वंदन योजना और कृषक इनपुट सहायता योजना बीजेपी के लिए प्लस प्वाइंट साबित हो सकता है। बीजेपी की कमजोरियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं है। बीजेपी के

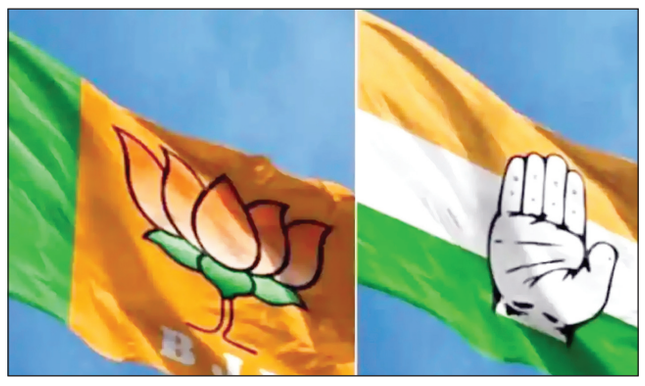

लिए अवसर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पुरानी सरकार और उसके घोटाले को लेकर लोगों को बीजेपी पुराने घोटालों की याद दिला सकती है। जबकि बीजेपी के लिए विपरीत स्थिति की बात करें तो महंगाई, बेरोजगारी और ट्रेनों के संचालन पर बीजेपी कांग्रेस से घिर सकती है।

कांग्रेस का SWOT फैक्टर क्या

कांग्रेस के SWOT फैक्टर की बात करें तो कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ियावाद है। पिछली कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, छत्तीसगढ़ियावाद (क्षेत्रीय कार्ड) और पूर्व सीएम बघेल की धरती पुत्र नेता के रूप में छवि कांग्रेस को लीड दे सकती है। पिछले पांच वर्षों में पार्टी ने बूथ स्तर तक अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत किया है। कांग्रेस की कमजोरियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राज्य इकाई कांग्रेस में गुजबाजी और अंदरुनी कलह पार्टी को परेशान कर सकती है। बघेल सरकार के खिलाफ लगे घोटाले के आरोप भी चिंता का विषय है। कांग्रेस के लिए अवसर की बात करें तो बीजेपी के नेताओं को केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करना पड़ता है जबकि कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लिए विपरीत स्थिति की बात करें तो कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर मोदी फैक्टर के जैसा कोई फैक्टर नहीं है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार का असर भी पड़ सकता है।

रायपुर रेलवे स्टेशन में जीएसटी विभाग का छापा

रायपुर। रायपुर रेलवे स्टेशन में जीएसटी ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक टीम ने सनशाइन केटर्स और टू व्हीलर पार्किंग में रेड मारी है। फिलहाल दोनों ही जगहों पर अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सन शाइन केटर्स के करीबी के दुर्ग स्थित ठिकाने में भी छापा पड़ा है।

बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन में संचालित सन शाइन कैटरर्स के स्टॉल के लाइसेंस फीस कैश में जमा किए जाने का मामला लल्लूराम डॉट कॉम ने उठाया था। लल्लूराम डॉट कॉम को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ में लिया गया जीएसटी नंबर उक्त फर्म का 2017 से बंद है।

सूत्रों की माने तो यहां कंपनी का कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। इतना ही नहीं इस फर्म के अलावा इनके परिवार की अन्य दर्जनों फर्म दुर्ग के अलावा पूरे देश में मौजूद है। लेकिन रेलवे में इनका तगड़ा जुगाड़ होने के कारण इनकी छत्र छाया में पूरा रेलवे डिपार्टमेंट फल-फूल रहा है और यही कारण है कि इसकी जांच अब तक नहीं हो रही है। सूत्र बताते है कि इस फर्म को पूर्व में जीएसटी की ओर से भी नोटिस जारी की गई थी।

कांग्रेस प्रत्याशी उपाध्याय ने लोगों से संपर्क साधने ट्रेन से की यात्रा

रायपुर। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय आज रेल यात्रा कर चुनाव प्रचार करने निकले। सुबह 7 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन से भाटापारा जाने वाली ट्रेन मेमो एक्सप्रेस का विकास उपाध्याय ने आम लोगों के साथ टिकिट काउंटर में लाइन लगकर टिकिट खरीदा और यात्रा की। इस दौरान विकास उपाध्याय ने लोकल ट्रेन से रोज आने जाने वाले यात्रियों के साथ चर्चा कर उनकी समस्या सुनी। वहीं लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।

विकास उपाध्याय ने बताया कि रायपुर लोकसभा के लिए 9 विधानसभा आते हैं और आज भाटापारा विधानसभा का दौरा है। तो आज लोकल ट्रेन में यात्रा कर भाटापारा के लिए जा रहा हूं। लोकल ट्रेन में डेली हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। लोकसभा का सांसद और सरकार इस रेल व्यवस्था में क्या स्थिति है और क्या रेल व्यवस्था होनी चाहिए उस पर जरूर बात करना चाहिए।

उन्होंने कहा आज मैंने ट्रेन में सफर करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी चर्चा की। मैं समझता हूं, जब ट्रेन में हम जाते हैं तो आपको सही में वस्तु स्थिति पता चलती है कि क्या किन समस्याओं के लिए आपको सरकार को बोलना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है इस रायपुर लोकसभा में नौ-आठ बार से बीजेपी का सांसद हैं। लेकिन ट्रेन की व्यवस्था के बारे में कोई भी सवाल नहीं उठाता। उन्होंने कहा कि हम छोटे थे हमने विद्याचरण शुक्ल को देखा था, जो रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए नई ट्रेनों को लाने का काम उन्होंने किया। अलग-अलग प्रदेशों को ट्रेन मार्ग से जोड़ने का काम किया और अब तक भाजपा की कोई उपलब्धि नहीं है। रेलवे स्टेशन आप चले जाएं शमशान घाट के समान रेलवे स्टेशन की स्थिति है।

महासमुंद लोकसभा सीट से क्या इस बार पंजा कमल को देगा मात?

महासमुंद। महासमुंद लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी लोकसभा सीट है। इस क्षेत्र में कभी कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन बीते डेढ़ दशक से बीजेपी ने यहां पर कब्जा जमा रखा है, बीते तीन लोकसबा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर लगातार जीत दर्ज की है। कांग्रेस इस सीट पर इस बार वापसी करने की कोशिश करेगी। महासमुंद से इस बार बीजेपी ने रुपकुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। जबकि कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है। रूपकुमारी चौधरी महासमुंद के बसना की रहने वाली हैं और वह यहां साल 2013 में विधायक भी रह चुकी हैं।

महासमुंद का सियासी इतिहास- महासमुंद को छत्तीसगढ़ की राजनीति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां से कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल सात बार सांसद रहे। श्यामा चरण शुक्ल और अजीत जोगी जैसे दिग्गज कांग्रेस नेता भी महासमुंद लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद साल 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चंदूलाल साहू ने कांग्रेस से ये सीट छीन ली। उसके बाद से बीजेपी यहां रेस में आ गई। हालांकि 1999 और 2004 में कांग्रेस की यहां पर जीत हुई। लेकिन उसके बाद से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है।

महासमुंद सीट का संसदीय इतिहास

1952 में कांग्रेस के शिवदास डागा ने जीत दर्ज की।

1962 में कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल सांसद बने। 1967 में फिर कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल जीते। 1971 में कांग्रेस के कृष्णा अग्रवाल की जीत मिली। 1977 में बीएलडी के बृजलाल वर्मा को जीत मिली। 1980 में कांग्रेस के विद्याचरण शुक्ल फिर सांसद बने। 1984 में कांग्रेस से विद्याचरण शुक्ल चौथी बार सांसद बने। 1989 में कांग्रेस से विद्याचरण शुक्ल पांचवी बास सांसद बने। 1991 में कांग्रेस के पवन दीवान जीते। 1996 में फिर कांग्रेस के पवन दीवान को जीत मिली। 1998 में बीजेपी के चंद्रशेखर साहू जीते। 1999 में कांग्रेस के श्यामा चरण शुक्ला की जीत हुई। 2004 में कांग्रेस के अजीत जोगी की जीत हुई। 2009 में बीजेपी के चंदूलाल साहू ने जीत दर्ज की। 2014 में बीजेपी के चंदूलाल साहू ने दोबारा जीत दर्ज की। 2019 में बीजेपी के चुन्नीलाल साहू ने जीत हासिल की।

महासमुंद लोकसभा सीट में कुल आठ विधानसभा सीटें हैं। जिसमें सरायपाली (एससी सीट), बसना, खल्लारी, महासमुंद, राजिम, बिंद्रानवागढ़, कुरुद और धमतरी की सीटें शामिल हैं। इन सबमें बिंद्रानवागढ़ (एसटी) विधानसभा सीटें हैं। इस सीट पर स्थानीयता और जातिवाद का मुद्दा हमेशा हावी रहता है। महासमुंद जिले में तीन नगर पालिका परिषद, तीन नगर पंचायत और पांच ब्लॉक मुख्यालय है।

बीते तीन लोकसभा में महासमुंद का मतदान प्रतिशत

2009 लोकसभा चुनाव- 56.7 फीसदी मतदान
2014 लोकसभा चुनाव- 74.61 फीसदी वोटिंग
2019 लोकसभा चुनाव- 74.63 फीसदी मतदान

महासमुंद की भौगोलिक स्थिति विकास और इतिहास पर नजर- महासमुंद की बात करें तो यहां आद्यौगिक विकास ज्यादा नहीं है। रेलवे कनेक्टिविटी की वर्षों पुरानी मांग आज भी यहां अधूरी है। महासमुंद से सरायपाली होते हुए बरगढ़ तक रेलवे लाइन की वर्षों पुरानी मांग अब भी पूरी नहीं हो पाई है। उद्योगों की कमी से यह इलाका जूझ रहा है। यह क्षेत्र पवित्र महानदी के तट पर स्थित है। यह सोमवंशीय सम्राट द्वारा शासित दक्षिण कोसल की राजधानी थी। यहां के मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं।अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल सिरपुर और गंगरेल बांध इस इलाके की शोभा बढ़ाते हैं। माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर यहां मेला लगता है।

कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमट सकती है

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस कांग्रेस का हमेशा अपर हैंड रहता था, वह अब दूसरों के रहम-ओ-करम पर राजनीति करने को मजबूर हो गई है। प्रदेश में ना उसका वोट बैंक बचा है, ना नेता और संगठन। हाँ, यदि हवा-हवाई बातों से पार्टी को फायदा हो पाता तो जरूर यूपी में कांग्रेस टॉप पर होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज का मतदाता अपने नेताओं पर बारीकी से नजर रखता है। इस कसौटी में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और गांधी परिवार पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। कांग्रेस के विधान सभा और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के आंकड़े भी चुनाव-दर-चुनाव उसके जनाधार खिसकने के साक्षी हैं। यह गिरावट 1984 के बाद चार दशक में आई है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 85 सीटों (तब उत्तराखंड की भी पांच सीटें शामिल) पर चुनाव लड़ी थी और 83 सीटों पर जीत हासिल की थी। भले ही तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के साथ जनभावनाओं का ज्वार था, जिसके सहारे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन के शिखर को छुआ। यह वह दौर था जब राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का एकछत्र राज था और बीजेपी की एंट्री भर हुई थी, लेकिन उसकी राजनैतिक विचारधारा कांग्रेस से उलट थी। बीजेपी तुष्टिकरण की जगह हिन्दुत्व की बात करती थी। अयोध्या, काशी और मथुरा उसके एजेंडे में प्रमुख रूप से शामिल थे, जिससे कांग्रेस हमेशा किनारा करती रही थी। वहीं क्षेत्रीय दलों के रूप में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। प्रदेश की राजनीति में बदले समीकरणों ने जहां दूसरे दलों के लिए नई संभावनाएं जगाईं, वहीं कांग्रेस को अपनों से मायूसी ही मिलती गई। 1984 में 51.03 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली कांग्रेस फिर ऐसे जनाधार को वापस नहीं हासिल कर सकी। आज उसका जनाधार दो प्रतिशत में सिमट गया है। दरअसल, प्रदेश में सपा व बसपा के उदय के साथ ही कांग्रेस पीछे होती गई और भाजपा की प्रखर हिंदुत्व वाली छवि ने उसकी राह और मुश्किल कर दी। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे। सपा के उदय के साथ मुस्लिम कांग्रेस से छिटक कर उसके पाले में चला गया। बसपा ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस से मोहभंग के बाद ब्राह्मणों ने भाजपा का दामन थाम लिया। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद की बात की जाए तो कांग्रेस वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर लड़ी थी और 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले ढाई दशक में यह कांग्रेस का सर्वाधिक उत्साहित करने वाला प्रदर्शन था। इसके पीछे कांग्रेस की मनरेगा व खाद्य सुरक्षा को लेकर नीतियों की बड़ी भूमिका मानी गई थी। कांग्रेस केंद्र में दोबारा सरकार बनाने में सफल हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी साख को बचाए रखने में कामयाब नहीं रही। उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिय पार्टी ने कई प्रयोग भी किए। राहुल गांधी को यूपी में पैर पसारने के लिये खुली छूट दी गई, इसके नतीजे उत्साहवर्धक नहीं आये तो प्रियंका वाड्रा को प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन बूथ स्तर पर कमजोर हुई पार्टी के सामने कार्यकर्ताओं में पुराना जोश भरना सपना ही रहा। उधर, कांग्रेसी नेता आपस में टांग खिंचाई करते रहे, जिसकी वजह से पार्टी में अंतरकलह भी बढ़ता गया। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 2009 का अपना प्रदर्शन दोहराने को तरसती ही रही। नेहरू-गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से गहरा रिश्ता होने के बाद भी पार्टी खोया दमखम नहीं जुटा सकी। पिछले चुनाव में कांग्रेस रायबरेली की एकमात्र सीट पर ही जीत का स्वाद चख सकी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी तक हार गये। जबकि रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी अबकी बार सदन में जाने के लिये राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं। इस बार वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने के साथ ही परंपरागत सीट अमेठी व रायबरेली में अपनी साख को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रही है। इससे निपटने के लिए पार्टी सपा से गठबंधन के तहत उसके हिस्से आईं 17 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है।

अपनी स्वतंत्रता का चुनाव करें

पी. चिदंबरम

अगर आदर्श रूप से देखें, तो किसी देश की सरकार चुनने के लिए चुनाव, दरअसल एक सामान्य राष्ट्रीय उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए होना चाहिए। लोग ए। लोग भले ही अपने वोट पार्टी %ए% या फिर %बी% और या फिर कई पार्टियों में बांट कर दें, लेकिन उद्देश्य समान होना चाहिए। वोटों का यह विभाजन स्वाभाविक और स्वस्थ है और यह कोई स्थायी बिगाड़ पैदा नहीं करेगा। भारत में शुरुआती कुछ चुनाव असंतुलित थे। कांग्रेस अकेला संगठित दल था।

जवाहरलाल नेहरू एक महान नेता थे। उस वक्त कांग्रेस के प्रतिरोध में कुछ ही आवाजे थीं। दो समान ताकत वाले प्रतिद्वंद्वियों के बीच पहला वास्तविक चुनाव 1977 में हुआ। आपातकाल के बाद की परिस्थितियों में जयप्रकाश नारायण विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाए। जनता पार्टी की जीत निर्णायक थी, लेकिन इसने भारतीयों को बांट दिया। उत्तरी राज्यों ने एक तरह से, तो दक्षिणी राज्यों ने दूसरी तरह से मतदान किया। उत्तर और दक्षिण का यह विभाजन 1977 से कायम है।

कुछ अपवादों के साथ बाद के चुनावों में भी उत्तर और दक्षिण के मतदान के तरीकों में फर्क रहा। हिंदी भाषी और हिंदी जानने वाले उत्तरी राज्यों में प्रमुख प्रतिद्वंद्विता कांग्रेस और भाजपा में रही। धीरे-धीरे, लेकिन मजबूती के साथ भाजपा यहां कांग्रेस से आगे निकल गई। लेकिन दक्षिण राज्यों की स्थितियां अलग थीं। 1977 के बाद हुए चुनावों में यहां के क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को चुनौती दी। तमिलनाडु में द्रमुकं और अन्नाद्रमुक, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी, तेलंगाना में

टीआरएस, कर्नाटक में जद (एस) और केरल में कम्युनिस्ट के नेतृत्व वाला एलडीएफ। भाजपा इस भीड़ भरी लड़ाई में घुसपैठ नहीं कर सकी। हालांकि कर्नाटक में उसने ऐसा किया, लेकिन नतीजे मिले-जुले ही रहे।

क्षेत्रीय दलों की सफलता ने उत्तर और दक्षिण के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। दरअसल, दक्षिणी राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा को लेकर बेहद सशंकित हैं। भाजपा को हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व की पार्टी के रूप में चित्रित करने में कांग्रेस से ज्यादा बड़ी भूमिका इन्हीं क्षेत्रीय दलों की रही है। क्षेत्रीय भाषा पर अभिमान, सभी धार्मिक समूहों की स्वीकार्यता और समाज सुधारकों की विरासत ने दक्षिणी राज्यों के लिए एक अलग रास्ता तय किया है। राजस्व के हस्तांतरण में कथित भेदभाव, क्षेत्रीय भाषाओं पर हिंदी का प्रभुत्व और भोजन, वस्त्र, संस्कृति इत्यादि मामलों में मान्यताओं के एक सेट को बढ़ावा देने से दक्षिणी राज्यों का संशय और गहराता है। इसके अलावा, भाजपा ने राज्यों की स्वायत्तता को कम करने वाले कई कानून बनाकर केंद्र-राज्य संबंधों में %केंद्रवाद% का जहर भी घोला %है। भाजपा ने कानूनों को हथियार बनाकर क्षेत्रीय दलों को कमजोर बनाने और उन पर काबू रखने के लिए खुलेआम उनका इस्तेमाल भी किया है। नतीजा, उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी दुर्भाग्यवश और बढ़ गई है।

कांग्रेस के प्रति भाजपा का दृष्टिकोण तो स्पष्ट है। वह कांग्रेस-मुक्त भारत चाहती है यानी ऐसा भारत जिसमें कांग्रेस का एक पार्टी के तौर पर अस्तित्व ही न हो। लेकिन गैर-कांग्रेसी दलों के प्रति भी उसका रवैया यहीं है। ऐसा महूसस होतां है कि वह कुछ समय के लिए किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन भले कर ले, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य उस पार्टी को खत्म करना ही है। जनता पार्टी, अकाली दल, आईएनएलडी, बसपा और जद (एस) सभी इसके उदाहरण हैं। इसने देश के उत्तरी-पूर्वी राज्यों की क्षेत्रीय पहचान एकदम खत्म कर दी है। एक समय पर इसने टीएमसी, वाईआरएससीपी और टीआरएस से दोस्ती की थी, लेकिन उसका लक्ष्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उन्हें खत्म करना था और है भी। महाराष्ट्र, ओडिशा और हरियाणा में भी लक्ष्य एक ही है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक समय रहते जाग गए। शिवसेना, एनसीपी %और जजपा देर से जागे। जल्द ही आएलडी, बीजेडी और टीडीपी को एहसास हो जाएगा कि अगर भाजपा केंद्र में मजबूत होती है, तो उनका क्या होगा।

भाजपा अपने मूल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से पार्टी को 370 सीटें देने के लिए कह रही है। हालांकि इसका हिंदुत्व अभियान अयोध्या और काशी तक सीमित नहीं रहने वाला। हिंदू मंदिरों के पास और मस्जिदों पर विवाद खड़ा किया जाएगा। ज्यादा शहरों और सड़कों का नाम बदला जाएगा। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 बीती 11 मार्च, 2024 की अधिसूचना के साथ जारी हुआ है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का जो प्रयोग किया गया, उसे दोहराते हुए संसद में कानून पारित किया जाएगा। संविधान में संशोधन करके एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को कानून बनाया जाएगा।

संघीय मूल्य और संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा और देश राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नजदीक पहुंच जाएगा, जिसमें सभी शक्तियां एक ही आदमी में केंद्रित होंगी। दुर्भाग्य से बहुत से लोग केंद्रीयवाद का स्वागत करेंगे, क्योंकि सच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारे परिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे में पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया गया है। विकास के नाम पर हम अमीरों को ज्यादा अमीर होते देखेंगे और निचले 50 फीसदी लोगों से कहेंगे कि वे कुल संपत्ति के तीन फीसदी और राष्ट्रीय आय के तेरह फीसदी हिस्से से संतुष्ट रहें। सामाजिक व सांस्कृतिक पराधीनता व उत्पीड़न जारी रहेगा। आर्थिक विषमताएं अधिक बढ़ेंगी।

ये कोई कल्पित डरावनी कहानी नहीं है। इतिहास हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता व विकास सुनिश्चित करने के लिए समय- समय पर शासन को बदलना जरूरी होता है। यूरोप और अमेरिका में भी ऐसा ही होता है। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के देशों ने यह सबक नहीं सीखा, तो आज सत्तावादी सरकारों से पीड़ित हैं। भारत में हमने सबक तो सीखे थे, लेकिन महसूस होता है कि हम उन्हें भूल चुके हैं। चीन, रूस, तुर्की और ईरान के उदाहरण सामने हैं। पूरी दुनिया भारत के चुनावों पर नजर रखे है।

कृपया इनसे सीखें

इस कैंटीन में महज 30 पैसे में भरपेट भोजन

भोजन में चावल, दाल, दो तरह की सब्जी, पापड़, दो कैला, सलाद, देशी मिठाई भी। कीमत महज 30 पैसे। जी हाँ, 30 पैसे। इसी तरह नाश्ते में नमकीन पूड़ी, प्याजी, लड्डू, हलवा, चने की घुघुनी, कचौड़ी और आलूचाप, हर आइ केवल छह पैसे में। यकीन नहीं आ रहा तो देखने के लिए चले आइए जमशीदपु यह टाटा मोटर्स की कैंटीन है। यहाँ हर दिन करीब पंद्रह हजार कर्मचारी इस

कैंटीन में आनंद उठाते हैं। दावा है कि विश्व की किसी भी सरकारी या गैर सरक कंपनी में इस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। मँहगाई के इस दौर में जहाँ कंपनियां है तरह की सुविधाओं में कटौती कर रही हैं, वहीं टाटा मोटर्स की यह कैंटीन 64 वर्षों के कॉरपोरेट जगत में अपने कर्मचारियों के

लिए सस्ता भोजन परोसकर नजीर पेश कर रही है। यह सुविधा न सिर्फ स्थायी बल्कि अस्थायी, प्रशिक्षु और ठेका कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है। कंपनी में नाश्ते और भोजन के लिए टोकन मिलता है। कर्मचारी एक हफ्ते के लिए इसे खरीद कर रख लेते हैं।

टाटा मोटर्स की इस अनूठी कैंटीन में प्रतिदिन करीब 15 हजार कर्मचारी भोजन करते हैं। इनमें स्थायी, अस्थायी, प्रशिक्षु कर्मियों की संख्या साढ़े दस हजार है। जबकि साढ़े चार हजार ठेका कर्मचारी हैं। इस कैंटीन में सिर्फ स्थायी कर्मचारियों को भोजन के लिए 60 पैसे यानी हर महीने में बीस रुपये चुकाने पड़ते हैं। शेष को सिर्फ 30 पैसे ही देने होते हैं। टाटा मोटर्स कंपनी वर्ष 1954 में स्थापित हुई थी। तभी इस कैंटीन की बुनियाद रखी गई थी। उसी समय से यहाँ कम कीमत पर भोजन और नाश्ता कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी पहले खुद इस कैंटीन को चलाती थी। अब इसे सोडेस्को नाम एजेंसी चला रही है। एजेंसी को इस एवज में टाटा मोटर्स कंपनी अनुदान देती है। प्रारंभिक दौर में टेल्को वर्कर्स यूनियन के महामंत्री रहे स्व. गोपेश्वर ने इस कैंटीन के लिए सर्वप्रथम पहल की थी। यह उन्हीं के दिमाग की उपज है। यूनियन के महामंत्री रहे चंद्रभान प्रसाद ने वर्ष 2010 में कंपनी के साथ ग्रेड रिवीजन के दौरान टोकन की जगह स्थायी कर्मचारियों के लिए वेतन से ही दस रुपये काट लेने की सुविधा लागू करा दी। वर्ष 2017 में 31 जुलाई को पुनः ग्रेड समझौता के दौरान स्थायी कर्मचारियों के लिए 60 पैसे की थाली तय कर दिए गए। पैसा वेतन से ही हर माह 10 की जगह 20 रुपये कटने लगा। नाश्ते की दर पूर्व की तरह प्रति आइटम छह पैसे जारी रहा। वहीं ठेका व प्रशिक्षु कर्मचारियों को भी पूर्व की तरह 30 पैसे के कूपन से ही भोजन मिल रहा है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-35)

गतांक से आगे...

जब चित्त विषय वासनाओं का त्याग कर देता है तथा सर्वत्र गमन करने वाला बन जाता है, तब उसकी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था ही आत्मा एवं परमात्मा के नाम से अभिहित होती है। अवश्य ही यह सभी कुछ ब्रह्म है। वह नित्य एवं चिद्घनस्वरूप है। वही अव्यय है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मन नाम की कल्पना की जाती है, उसका कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है। वह तो मात्र भ्रम ही है। इन तीनों लोकों में न तो किसी का जन्म होता है और न ही मृत्यु। ये जो भी भाव-विकार दृष्टिगोचर होते हैं, ये सभी अस्तित्वहीन हैं। एकमात्र केवलाभासरूप, सर्वव्यापी, अव्यय तथा चित्त के विषयों का अनुगमन न करने वाले केवल चिन्मात्र की ही सत्ता यहाँ विद्यमान है। उस नित्य, सर्वत्रव्यापी, शुद्ध, चिन्मात्र, उपद्रव रहित, शान्तस्वरूप एवं शमरूप में स्थित विकाररहित चिदात्मा में स्वयंचित्त ही स्वभावानुसार संकल्पपूर्वक गमन करता है, चित्त की वही संकल्परूप अवस्था स्वयं निर्दोष होते हुए भी मनन करने के कारण मन कही जाती है। इस कारण संकल्प के द्वारा सिद्ध मन संकल्प द्वारा ही विनष्ट हो जाता है मैं ब्रह्म नहीं हूँ ऐसा सुदृढ़ संकल्प हो जाने से मन बन्धन-ग्रस्त नहीं होता और यह सभी कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा दृढ़ निश्चयी संकल्प हो जाने पर मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मैं क्षीणकाय हूँ, दुःखों से ग्रस्त हूँ, मैं हाथ पैर से युक्त हूँ, इस प्रकार के भावानुकूल व्यवहार से प्राणी बन्धनग्रस्त हो जाता है। मैं दुःखी नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं, आत्मतत्त्व में प्रतिष्ठित मुझमें बन्धन कहाँ? इस प्रकार के व्यावहारिक जीवन से ओत-प्रोत मन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मैं मांस नहीं हूँ, अस्थि नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर जिसके अन्तस् से अविद्या नष्ट हो गयी है, वही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। पदार्थों में आत्मभावना होना ही अविद्या जनित कल्पना है। **(क्रमशः)**

आजाद हिंद फौज ने उत्तर पूर्व में आकर पहली बार फहराया था तिरंगा

भारत की आजादी के संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुआई में आजाद हिंद फौज का अपना प्रभाव रहा है। पूरी दुनिया जब द्वितीय विश्व युद्ध में उलझी थी तब भारत की आजादी के लड़ने वाला एक बड़ा तबका अंग्रेजों के खिलाफ होने के साथ फासिस्ट ताकतों के भी खिलाफ था। इसी बीच नेताजी ने इसे एक अवसर की तरह देखा और भारत की एक सेना तैयार कर उसमें ऐसा जोश भरा जो सिंगापुर से होते हुए पूर्वोत्तर में दाखिल होने में कामयाब रही। यह पहला मौका था जब देशवासियों ने फौजी अंदाज में अंग्रेजों से अपनी जमीन वापस ली थी।

आजाद हिंद फौज के मिलने से पहले भी नेताजी को अथक प्रयास करना पड़ा। अंग्रेजों को चकमा देते हुए अफगानिस्तान रूस के रास्ते जर्मनी पहुंचना वहां निराशा हाथ लगने पर सिंगापुर पहुंचना एक

संघर्षपूर्ण यात्रा थी। सिंगापुर में उन्हें आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने का मौका मिला और उन्होंने जापान से हाथ मिलाकर फौज के साथ भारत की ओर कूच किया।

19 मार्च 1944 को कर्नल शौकत मलिक ने कुछ मणिपुरी और आजाद हिंद के साथियों की मदद से पूर्वोत्तर में देश की जमीन में प्रवेश किया और वहां उस समय फौज द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय झंडा फहराया था। कर्नल शौकत अली मलिक ने इस लड़ाई में आजाद हिंद फौज की बहादुर रेजिमेंट का नेतृत्व किया था। इसी घटना पर बिमल राय ने पहला आदमी नाम की फिल्म भी बनाई थी।

इस घटना के दो दिन बाद ही नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और बाद में मोइरंग में 14 अप्रैल को आजाद हिंद फौज ने मोइरांग पर कब्जा किया जहां कर्नल मलिक ने तिरंगा फहराया। मोइरांग को ही आजाद हिंद फौज का भारतीय मुख्यालय बनाया गया। यह सब मणिपुरी लोगों की मदद से संभव हो सका था यहां आज भारत की स्वतंत्रता के उस संघर्ष को दर्शाता एक भारतीय राष्ट्रीय सेना संग्रहालय भी है।

इसके बाद फौज को एक साथ बहुत सारी दिक्कतों का सामाना करना पड़ा।बारिश ने आने जाने में मुश्किलें बढ़ाई और जवानों की सेहत पर असर होने लगा। रसद के पहुंचने में दिक्कत तो हो रही थी संचार में बहुत मुश्किल होता गया। जापानी सेना से भी मदद ढीली होती गई। इस सब की वजह से आजाद हिंद फौज को जापानी सेना के साथ पीछे हटना पड़ा और जंग अंग्रेजों को भारी पड़ने का मौका मिलता गया।

रोचक बात यह है कि जो तिरंगा कर्नल शौकत मलिक ने फहराया था वह तिरंगा वह झंडा नहीं है जो आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। यह झंडा कुछ अलग था इसमें नारंगी सफेद और हरे रंग की तीन पट्टियां तो थी, लेकिन सफेद पट्टी ज्यादा चौड़ी थी जिसके बीचों बीच एक उछलता हुए बाघ की तस्वीर थी। इसके अलावा पहली नारंगी पट्टी पर आज़ाद और निचली हरी पट्टी पर हिन्द लिखा हुआ था। आजाद हिंद फौज का संघर्ष और आजादी पाने का जुनून देशभक्ति की एक बड़ी मिसाल है।

एल डोराडो खतरे में है, पुतिन की नजर से उभरी है आशंका

अंशुमान तिवारी

स्वीडन मार्च के दूसरे सप्ताह में नाटो का 32वां सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री उल्फ क्रीत्सेरसॉन ने वाशिंगटन में नाटो की सदस्यता हासिल की। इसके साथ स्वीडन ने करीब दो सौ साल पुरानी कूटनीतिक तटस्थता को खत्म कर दिया। रूस व अमेरिका के लंबे शीतयुद्ध के दौरान स्वीडन तटस्थ रहा, मगर यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप में खौफ पेसरा है। वर्ष 2022 की जनवरी की बात है, तब तक यूक्रेन पर रूस का कहर शुरू नहीं हुआ था। बाल्टिक सागर में रूस के छह जंगी जहाज गश्त करते नजर आए।

लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा पर कैलिनिनग्राद में रूस का नौसैनिक अड्डा है। ये जहाज यहीं से आए थे। स्वीडन की पुलिस को पता चला कि स्वीडन के नाभिकीय संयंत्रों के आसपास कई ड्रोन देखे गए हैं। चौबीस घंटे के भीतर ही स्वीडन ने गोटलैंड के द्वीप पर सैन्य तैनाती में जबर्दस्त बढ़ोतरी कर दी। गोटलैंड पर इस कदर सैन्य तैनाती शीतयुद्ध के दशकों में भी नहीं देखी गई थी।

रूस और स्वीडन के रिश्तों का इतिहास ही लंबी शत्रुता का है। 12वीं से 19वीं सदी तक रूस और स्वीडन के बीच करीब एक दर्जन युद्ध हुए हैं और कड़वाहट अब भी जारी है। यूक्रेन पर हमले के बाद स्वीडन गोटलैंड द्वीप पर रूस के हमले को लेकर बेहद सशंकित है। यही डर उसे शताब्दी पुरानी कूटनीतिक तटस्थता छोड़कर नाटो की शरण में ले आया है। गोटलैंड बाल्टिक सागर में इतिहास का सबसे जीवंत स्मारक है। बांधिए कुर्सी की पेटी, टाइम मशीन अब रूस होते हुए गोटलैंड की तरफ उड़ान भरने को तैयार है।

टाइम मशीन 16वीं-17वीं सदी में उड़ान भर रही है। ठीक पहचाना आपने यह रूस के पहले जार

आइवन द टेरबिल हैं, जो मध्ययुगीन मस्कोवी शासन को रूस के दक्षिण में फैला रहे हैं। आइवन द टेरबिल ने मध्य एशिया से लेकर काला सागर के तट तक तातारों-कजाकों के शासन वाले इलाके और अस्त्राखान के खानेत को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। मगर इतिहास तो अब बनना शुरू हुआ है। अपनी सीट के सामने लगी स्क्रीन पर देखिए। यह 1708 का साल है।

रूस की जानलेवा ठंड के बीच स्वीडन के सम्राट चार्ल्स बारहवें की सेना यूक्रेन के दक्षिण की तरफ बढ़ रही है। स्वीडन के सम्राट चार्ल्स पहले भी रूस की सेना को धूल चटा चुके थे, लेकिन मास्को उनकी पहुंच से दूर रहा। सम्राट की सेना सर्दी से हार रही थी। फिर भी हमला जारी था। पीटर द ग्रेट ने चार्ल्स को रोकने के लिए पोल्टावा के किले से जवाब देना शुरू कर दिया। 1708 में जंग की शुरुआत हुई। पहली मुठभेड़ भारी पड़ी। रूसी सेना की गोलाबारी में स्वीडन के सम्राट चार्ल्स घायल हो गए। किसी तरह जान तो बच गई, अलबत्ता सम्राट युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए सेना की कमान फील्ड मार्शल कार्ल गुस्ताव रेंकिओल्ड और जनरल लुडविग ल्यूनहॉप्ट को दे दी गई।

इस इलाके पर मंडराते हुए हमें दिखेगा कि एक माह तक अलग-अलग मोर्चों पर स्वीडन और रूस की सेना के बीच भयानक जंग हुई। मगर स्वीडन की सेना टिक नहीं पाई। 10,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए या कैद कर लिए गए। स्वीडन के सम्राट चार्ल्स को दक्षिण में ओटोमन साम्राज्य के इलाके में शरण लेनी पड़ी। पोल्टावा की हार के साथ स्वीडन के साम्राज्य विस्तार की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई। पीटर द ग्रेट काला सागर से लेकर बाल्टिक तट तक राज करने लगे।

टाइम मशीन अब बाल्टिक तट पर सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर उड़ान भर रही है। स्वीडन हार तो गया, लेकिन पीटर द ग्रेट बाल्टिक सागर से उस पार नहीं जा सके। वह रूस के साम्राज्य को यूरेशियन सीमा से निकाल कर बाल्टिक के दूसरी ओर ले जाना चाहते थे। इसी कोशिश में उन्होंने 1703 में बाल्टिक तट पर सेंट पीटर्सबर्ग शहर बसाया था। बाल्टिक सागर में स्वीडन की ताकत अकूत थी, जिस पर रूस का जोर नहीं चला। ... और अब हम आ गए हैं गोटलैंड पर। स्टॉकहोम के तट से पूर्व की ओर स्थित गोटलैंड पहुंचने में करीब पांच घंटे लगते हैं। यह हिसाब 21वीं सदी का है।

एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपनी शुरुआत करने वाले छोटे से गोटलैंड पर साम्राज्यवादियों के असंख्य निशान दर्ज हैं। टाइम मशीन अब और पीछे 14वीं सदी से 16वीं सदी की तरफ जा रही है, जब इस द्वीप पर प्रत्येक शताब्दी में किसी न किसी साम्राज्यवादी शासक ने कब्जा किया। कभी जर्मन, तो कभी डैनिश, तो कभी रूसी कब्जे से गुजरते हुए गोटलैंड स्वीडन का हुआ। टाइम मशीन में बैठने से पहले शायद आपने सुना हो कि नाटो में स्वीडन के प्रवेश से गुस्साए पुतिन अपने बाल्टिक अभियान में गोटलैंड को निशाना बना सकते हैं। गोटलैंड सुंदर तो है ही, अनोखा और मूल्यवान भी है। इसलिए टाइम मशीन आज आई है। पूर्वी यूरोप और बाल्टिक के इलाके में यह उन गिने-चुने इलाकों में से है, जहां मनुष्य के रहने के प्रमाण 8,000 से 6,000 साल पुराने हैं। आइए, 800 से 1150 के युग में चलें।

गोटलैंड वाइकिंग लड़ाके जंग की तैयारी करते दिखेंगे। मगर सबसे दिलचस्प बात यह कि गोटलैंड वाइकिंग का एल डोराडो था। एल डोराडो एक ऐसे शहर की कल्पना है, जहां खजाने दबे हैं। समय के इस दौर में आपको वाइकिंग यहां सोना ढोते दिख जाएंगे। टाइम मशीन की स्पीड बढ़ाते हैं और हम आ गए आठवीं से बीसवीं सदी में। बात 1999 की है, स्वीडिश न्यूज टीवी की एक टीम को चांदी के करीब 150 सिक्कों और पुरातात्विक कांस्य सामग्री की चोरी के बारे में पता चला है।

पुरातत्वविदों की सलाह पर इस टीम ने खोज जारी रखी। जमीन से तीन मीटर नीचे चांदी के सिक्कों का एक बड़ा भंडार मिल गया। गोटलैंड में खबर फैल गई। वर्ष 1999 के बाद के दशकों में गोटलैंड पर वाइकिंग के 700 खजाने मिल चुके हैं। इन खजानों ने पहली बार सिद्ध किया कि वाइकिंग यूक्रेन और रूस पार कर बाइजेंटियन साम्राज्य की सीमाओं तक जाते थे। स्वीडिश पुरातत्व के जानकार मानते हैं कि बांइकिंग खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा गोटलैंड की जमीनों के भीतर दबा है। रॉबर्ट डी कपलान ने अपनी किताब द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में दुनिया के उन अभिशप्त और विवादित भूगोलों का जिक्र किया है, जिनका इतिहास उन्हें कभी भी नए युद्धों से मिलवा सकता है। गोटलैंड इसी तरह का भूगोल है, जो फिर विस्फोटक हो चला है।

आज का इतिहास

1932 सिडनी हार्बर ब्रिज , ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख स्थल, सिडनी, और दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च ब्रिज खोला गया था।
1941 यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर कॉर्प्स की पहली अखिल अफ्रीकी अमेरिकी इकाई टस्केगी एयरमेन को सक्रिय किया गया।
1954 अमेरिकी पूल (पॉकेट बिलियर्ड्स) खिलाड़ी विली मोस्कोनी एक प्रदर्शनी सीधे पूल के दौरान 526 लगातार गेंदों से चूक गए।
1962 अत्यधिक प्रभावशाली अमेरिकी संगीतकार बॉब डायलन ने अपना पहला एल्बम जारी किया।
1962 बॉब डायलान का पहला एल्बम संयुक्त राज्य में जारी किया गया।
1970 पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के नेता 1949 में जर्मनी के विभाजन के बाद पहली बार मिले।
1978 लेबनान पर इजरायल के आक्रमण के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र ने इज़रायल से अपनी सेना को तुरंत वापस लेने के लिए कहा, और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल की स्थापना की।
1987 अमेरिकी टेलीविज़नवादी जिम बेकर ने एक सेक्स स्कैंडल के बीच ThePTL क्लब के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे दिया।
1990 रोमानिया के त्रेगुर म्योर में रोमानियन और हंगेरियन के बीच जातीय संघर्ष हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए।
1990 कनाडा की राजधानी ओटावा में महिलाओं की पहली विश्व आइस हॉकी प्रतियोगिता आयोजित हुई।
1994 जापान के योकोहामा में एक लाख 60 हजार अंडों से विश्व का सबसे बड़ा 1383 वर्गफुट आकार का आमलेट तैयार किया गया।
1995 प्लायमाउथ थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में अनुवाद खुल गया। इसने 25 प्रदर्शन किए हैं।
1995 फीनिक्स के बाहर एरिज़ोना नए क्षेत्र कोड 520 का उपयोग शुरू करता है।
1995 ब्रिटिश स्केट्स के बोनी ब्लेयर महिला विश्व रिकॉर्ड बिंदु कुल (156.450)।
1996 विनी मंडेला ने शादी के 38 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को तलाक दिया।

क्यों बदल रहा है चुनावी चंदे का स्वरूप?

संजय तिवारी

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्ती के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब अपनी वेबसाइट पर अपलोड तो कर दिया लेकिन किया ऐसे कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब हिसाब भी सार्वजनिक कर दिया लेकिन किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ही बड़ी चालाकी से छिपा लिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी की गयी जानकारी दो हिस्से में है। पहले हिस्से में उन कंपनियों का नाम है जिन्होंने चुनावी बॉंड खरीदकर चंदा दिया और दूसरे हिस्से में उन दलों का नाम है जिन्हें चंदा मिला। कितने मूल्य के बॉंड किस कंपनी ने खरीदे और कितना पैसा किस दल को मिला यह तो बताया गया है लेकिन यह नहीं बताया गया है कि किस कंपनी ने किस दल को कितना पैसा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पकड़ लिया। शुक्रवार को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एसबीआई से पूछा कि आपने ऐसी लिस्ट क्यों तैयार की जिससे यह पता ही न चले कि किस कंपनी ने किस दल को कितना चंदा दिया? असल में राजनीतिक दलों में व्याप्त भ्रष्टाचार तो खत्म करने के लिए जो चुनावी बॉंड वाला सिस्टम लाया गया था उसे बहुत गोपनीय रखा गया था। इस गोपनीयता को बनाये रखने के लिए ही कंपनियां बॉंड खरीदकर किस दल को दे रही हैं इसे जानने का सिर्फ एक जरिया था कि उसके आगे एक कोड नंबर डाल दिया जाना था। अगर कंपनी, बैंक के बॉंड और पार्टी के बीच से वह कोड मिस कर दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि किस कंपनी ने किस दल को कितना चंदा दिया। आप समग्रता में तो जान सकते हैं कि किस दल को कितना पैसा मिला लेकिन किस कंपनी ने वो पैसा दिया, इसे नहीं जान सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की इस चालाकी को पकड़ लिया और आदेश दिया कि रविवार शाम तक वो जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए और उसी दिन शाम 5 बजे तक उसे वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। यह हुआ या नहीं इसे जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सोमवार को फिर से एसबीआई के प्रतिनिधि को कोर्ट में बुलाया है। एसबीआई और चुनाव आयोग की हीला हवाली बता रही है कि वो चुनावी चंदे को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं करना चाहते। ऐसा वो किसके दबाव में कर रहे हैं यह तो वो ही जानें लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर सख्ती नहीं बरती होती तो उतनी जानकारी भी सामने नहीं आ पाती जितनी अब तक आयी है।

1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद सिर्फ अर्थव्यवस्था भर नहीं बदली है। समाज और राजनीति के स्वभाव में भी परिवर्तन हुआ है। हमारी जैसी अर्थव्यवस्था होती है वैसी ही हमारी राजनीति और समाज बन जाता है। अर्थ अकेले नहीं बदलता। वह पूरे परिवेश को बदल देता है। इसलिए आर्थिक उदारीकरण के बाद सिर्फ समाजवादी युग की सरकारी कंपनियों की ही विदाई नहीं हुई। राजनीति के उस तरीके की भी विदाई हो गयी जिसमें कॉरपोरेट घरानों या कंपनियों से चंदा लेना राजनीतिक भ्रष्टाचार समझा जाता था। ऐसा समझा जाता था कि अगर कोई सत्ताधारी दल किसी निजी कंपनी से चंदा ले रहा है तो निश्चित ही वह उसे अतिरिक्त लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा। संजय गांधी की मारुति मोटर्स को 1971 में जब जनता की कार बनाने का लाइसेंस दिया गया था तब विपक्ष ने बहुत हंगामा किया

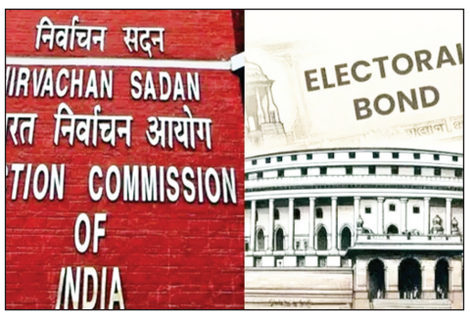

था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने ही बेटे की कंपनी को कार बनाने का लाइसेन्स कैसे दे सकती हैं? उस समय औद्योगिक उत्पादन का मतलब सरकारी कंपनी होता था और निजी कंपनियों को हेयदृष्टि से देखा जाता था। इसलिए राजनीतिक दल भी निजी कंपनियों से बहुत नजदीकी दिखाने से बचते थे। मारुति कंपनी ने भले संजय गांधी की मौत के बाद सुजुकी के साथ मिलकर देश की पहली जनता की कार बनाई हो लेकिन उस समय 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने ही संजय गांधी की मारुति मोटर्स को हरियाणा के मानेसर में 12 हजार रूपये एकड़ के हिसाब से जमीन का आवंटन किया था। कांग्रेस की ही सरकार में गुड़गांव में डीएलएफ रियलिटी को हजारों एकड़ जमीन दी गयी ताकि वह एक शहर बसा सके। इसी तरह रिलायंस के उत्थान में कांग्रेस के प्रणव मुखर्जी और मुरली देवड़ा का हाथ माना जाता है। हालांकि इसके कारण कांग्रेस को हमेशा आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा।

लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद परिस्थितियां एकदम बदल गयीं। अब कॉरपोरेट घरानों के हित में काम करना राष्ट्रीय विकास की गारंटी बन गया। अगर केन्द्र की कोई भी सरकार देश का या फिर राज्य की सरकारें अपने प्रदेश का विकास करना चाहती हैं तो लाल कालीन बिछाकर निजी कंपनियों का स्वागत करती है। उनकी जरुरतों के मुताबिक कानूनों में बदलाव करती हैं। अपने राज्य को ईज आफ डूइंग बिजनेस के मानकों पर खरा उतराने के लिए कॉरपोरेट घरानों की हर मांग को पूरा करने का प्रयास करती हैं।

इंदिरा गांधी सरकार ने भले ही अपने बेटे की कंपनी को 12 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से जमीन दी हो लेकिन आज सरकारें कंपनियों को मुफ्त जमीन, बिजली, पानी और टैक्स में छूट देकर किसी भी तरीके से अपने राज्य में ले आना चाहती हैं। माहौल ऐसा बन गया है कि अगर देश की आर्थिक तरक्की करनी है तो कॉरपोरेट घरानों के आगे घुटने टेककर भी उन्हें अपने यहां फैक्टरी लगाने के लिए मना लेना है।

मतलब अर्थनीति बदली तो निजी कंपनियों को लेकर सरकारी रुख भी बदल गया। नरेन्द्र मोदी ने लखनऊ में साफ कहा ही था कि अब वो समय गया जब नेता कंपनियों से अपने रिश्तों को छिपाते थे। कंपनियां अर्थव्यवस्था को संचालित कर रही हैं, लोगों को नौकरी रोजगार दे रही हैं फिर उनसे रिश्तों को छिपाने की जरूरत क्या है? लेकिन कहीं न कहीं हमारे राजनीतिज्ञों के मन में राजनीतिक शुचिता की एक फांस फंसी हुई है और लाख कहने के बाद भी वो कंपनियों से अपने निजी रिश्तों को छिपाते हैं। यही कारण है कि जब मोदी पर अडानी की कंपनियों का फेवर करने का आरोप लगा तो वो जवाब देने के लिए कभी सामने नहीं आये।

कुछ ऐसा ही हाल इस समय चुनावी बॉंड को लेकर भी है। विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह उलटे विपक्ष को ही चुनौती दे रहे हैं कि बीजेपी को 6 हजार करोड़ मिले हैं जबकि उसके पास 303 सांसद हैं। वहीं विपक्ष को उनसे ज्यादा मिले हैं जबकि उनके 242 सांसद ही हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश चुनावी बॉंड के जरिए मिले बीजेपी के 6 हजार करोड़ पर सवाल तो उठाते हैं लेकिन साथ में यह भी बताते हैं कि उनकी पार्टी को भी 1400 करोड़ रुपए मिले हैं।

यहां एक बात गौर करनेवाली है कि उन्हीं राजनीतिक दलों को चुनावी बॉंड के जरिए सर्वाधिक चंदा मिला है जो केन्द्र या फिर किसी राज्य की सत्ता में हैं। इससे इतना तो साफ है कि कॉरपोरेट हाउस पैसा उन्हें ही देते हैं जो सत्ता में होते हैं या फिर जिनके सत्ता में आने की संभावना होती है। अपने कारोबार में पाई पाई का हिसाब रखनेवाली कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जनता के लिए इससे महत्वपूर्ण सवाल दूसरा है। वह यह कि क्या आर्थिक उदारीकरण के इस चढते दौर में जो राजनीतिक कॉरपोरेट गठजोड़ हो रहा है उसे ही मान्यता दिलाने के लिए चुनावी बॉंड की व्यवस्था शुरु की गयी? अगर ऐसा था तो भाजपा या दूसरे सत्ताधारी दलों के नेता इसे स्वीकार करने से भाग क्यों रहे हैं? उनका सच्चाई से भागना ही सवाल खड़ा करता है कि पर्दे के पीछे वो कंपनियों से चाहे जो डील करें लेकिन पर्दे के सामने उसे स्वीकार करने का उनमें साहस नहीं है। उन्हें भी लगता है कि ऐसा करने पर उनकी या उनकी पार्टी की छवि धूमिल होगी। राजनीतिक दलों का यही संकोच यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उन्होने जो किया वह राजनीति कॉरपोरेट गठजोड़ का मिला जुला भ्रष्टाचार ही था। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इसे निरस्त कर दिया है बल्कि इसकी सक्रियता की वजह से ही चुनावी चंदे का सच भी सामने आ पाया है।

धार्मिक रूप से उत्पीड़ितों को अपनाने के लिए बना कानून है सीएए

अवधेश कुमार

सीएए और नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने पर हो रही प्रतिक्रियाएं वही हैं जैसी संसद में पारित होने के पूर्व से लेकर लंबे समय बाद तक रही हैं। यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि आखिर ऐन चुनाव के पूर्व ही इसे लागू करने की क्या आवश्यकता थी? अगर लागू नहीं किया जाता तो चुनाव में विरोधी यही प्रश्न उठाते कि इसे लागू क्यों नहीं कर रहे? हालांकि आम लोगों के मन में यह प्रश्न उठेगा कि इतना समय क्यों लगा? कानून पारित होने के बाद नियम तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय को सात बार विस्तार प्रदान किया गया था। नियम बनाने में देरी के कई कारण रहे। कानून

पारित होने के बाद से ही देश कोरोना संकट में फंस गया और प्राथमिकताएं दूसरी हो गईं। दूसरे, इसके विरुद्ध हुए प्रदर्शनों ने भी समस्याएं पैदा कीं। अनेक जगह प्रदर्शन हिंसक हुए, लोगों की मौत हुई और दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे तक हुए। तीसरे, विदेशी एजेंसियों और संस्थाओं की भी इसमें भूमिका हो गई। चौथे, उच्चतम न्यायालय में इसके विरुद्ध याचिकाएं दायर हुईं। इन सबसे निपटने तथा भविष्य में लागू करने पर उनकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी व्यवस्था करने में समय लगना ही था। मूल बात यह नहीं है कि इसे अब क्यों लागू किया गया। मूल यह है कि इसका क्रियान्वयन आवश्यक है या नहीं और जिन आधारों पर विरोध किया जा रहा है क्या वे सही हैं? यह बताने की आवश्यकता नहीं कि कानून उन हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के लिए है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण पलायन कर भारत आने को विवश हुए थे यानी यह कानून इनके अलावा किसी पर लागू होता ही नहीं। भारत में नियमों के तहत आवेदन कर कोई भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। केवल इस कानून के तहत इन समुदाय के लोगों के लिए नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाया गया है। यह आशंका ही निराधार है कि इससे किसी को बाहर निकाला जाएगा। सीएए गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशियों या किसी को निकालने के लिए नहीं लाया गया है। इसके लिए विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 पहले से है। नागरिकता कानून, 1955 के अनुसार अवैध प्रवासियों को या तो जेल में रखा जा सकता है या वापस उनके देश भेजा जा सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इनमें संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रुकने तथा कहीं भी आने-जाने की छूट दे दी थी तो विशेष प्रावधान के द्वारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक में खाता खुलवाने, अपना व्यवसाय करने या जमीन तक खरीदने की अनुमति दी गई। इस तरह उन्हें भारत द्वारा अपनाने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी।

हरियाणा में खट्टर को थोड़ा पहले ही विदा कर देना चाहिए था

चेतनादित्य आलोक

आमतौर पर राजनीति के क्षेत्र में आने वाले तूफानों की भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल कार्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक तूफानों का पुरोवाक् लिखना बहुत कम लोग ही जानते हैं... और जो जानते हैं वे तूफानों के आने पर विचलित नहीं होते, बल्कि शांत और प्रसन्न किंतु गतिशील बने रहते हैं। देखा जाए तो मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कुछ-कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल, घटनाक्रम कुछ इस प्रकार आगे बढ़ा कि 11 मार्च को गुरुग्राम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भूरी-भूरी प्रशंसा की और दूसरे दिन दोपहर तक खट्टर सरकार से बाहर हो गए या कर दिए गए, जिसे जो उचित लगे उसे वही समझ लेने की यहां पूरी गुंजाइश है। गौरतलब है कि खट्टर के साथ व्यतीत किए गए अपने पुराने दिनों की याद ताजा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मनोहर लाल की प्रगतिशील मानसिकता के बारे में खुलकर बात की थी। गुरुग्राम में खट्टर के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने कहा- %जब दरी पर सोने का जमाना था, तब भी हम साथ थे। उस समय इनके (खट्टर के) पास एक मोटरसाइकिल थी। हम लोग उसी पर सवार होकर हरियाणा भ्रमण करते थे।% प्रधानमंत्री ने कहा कि खट्टर मोटरसाइकिल चलाते थे और वे पीछे बैठा करते थे। हम रोहतक से निकलते थे और गुरुग्राम आकर रुकते थे।

आश्चर्य होता है कि 11 मार्च को प्रधानमंत्री ने ये बातें कहीं और 12 मार्च को सुबह अचानक ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जननायक जनता पार्टी (जजपा) के बीच दरार एवं मुख्यमंत्री खट्टर के इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई। दृश्य मीडिया जगत् यानी टीवी के खबरों की दुनिया में यह खबर सनसनी की तरह फैली और जब तक यह अपना पूरा प्रभाव छोड़ती तब तक यह खबर अपनी अंतिम परिणति तक पहुंच चुकी थी। तात्पर्य यह कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका था। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्यमंत्री खट्टर को तो जाना ही था, बल्कि सच कहा जाए तो उन्हें थोड़ा और पहले जाना चाहिए था। इससे नई सरकार को जनता के बीच अपना फेस-ऑफ करने तथा

काम के बल पर अपनी इमेज बनाने का भरपूर समय मिल सकता था। गौरतलब है कि खट्टर का दूसरा कार्यकाल इसी वर्ष अक्तूबर में पूरा होना था। जाहिर है कि अक्तूबर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगभग 69 वर्षीय थके-हारे से दिखाई देने वाले सहज और सरल स्वभाव के स्वामी मनोहर लाल खट्टर के भरोसे भाजपा हरियाणा के दंगल में नहीं उतरना चाहती थी। यही नहीं, कुछ ही महीने पूर्व हरियाणा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान मुख्यमंत्री खट्टर का ढिलाई से पेश आना भी उनकी विदाई का एक बड़ा कारण रहा है। दरअसल, सांप्रदायिक दंगे के प्रति उनके सख्त नहीं होने से सरकार की छवि धूमिल हुई थी, जो भाजपा सुप्रीमो को रास नहीं आया था।

इसके अतिरिक्त खट्टर को हटाए जाने का एक प्रमुख कारण राज्य में लगभग 10 वर्षों तक सत्ता की बागडोर संभालने वाली खट्टर सरकार के विरुद्ध एंटी इंकम्बैंसी का फैक्टर भी माना जा रहा है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की विदाई के बाद मनोहर लाल खट्टर की विदाई भी लगभग तय ही मानी जा रही थीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान की छवि बेहद अच्छी मानी जा रही थी। साथ ही शासन और प्रशासन में उनकी भूमिका भी किसी प्रकार के वाद-विवाद अथवा संदेह से परे थी। उसके बावजूद जब उन्हें बैठा दिया गया, तब भला मनोहर लाल खट्टर की विदाई कैसे नहीं होती। वैसे शिवराज सिंह और मनोहर लाल, दोनों को इस बार पार्टी ने एक ही तरीके से सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों घटनाओं में कई समानताएं भी हैं, यथा दोनों को अचानक हटाया जाना, दोनों के करीबियों को ही मुख्यमंत्री के रूप में चुना जाना और इन दोनों के हाथों ही नए मुख्यमंत्रियों को मुस्कुराते हुए ताज पहनवाना आदि। हालांकि दोनों घटनाओं में एक बड़ा अंतर भी है और वह यह कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की मुस्कराहटों में बड़ा अंतर था। एक ओर जहां शिवराज सिंह चौहान की मुस्कराहट के पीछे कुछ खोने का दर्द और अफसोस का भाव स्पष्ट देखा जा सकता था, वहीं, मनोहर लाल खट्टर की मुस्कराहट हमेशा की तरह सहज, सरल और शालीन बनी हुई थी। गौरतलब है कि राजनीति में मुस्कराहटों का अपना एक फलसफा होता है। ये मुस्कराहटें बहुत कुछ कहती हैं। ये पीछे छूट चुके समय के दर्द और दुख को तो बताती ही हैं, साथ ही आगत खुशियों और परेशानियों को भी बयां करने में सक्षम होती हैं।

गौर करें तो उपर्युक्त दोनों घटनाओं में ऐसा ही हुआ है। जहां शिवराज सिंह चौहान नाराज और दुखी हैं, वहीं मनोहर लाल खट्टर खुश और आश्वस्त हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद दोनों नेताओं की भाव-भंगिमाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह अपनी विदाई को लेकर अनजान थे, जबकि मनोहर लाल को पता था कि अब राज्य में उनकी भूमिका खत्म हो गई है और केंद्र में मोदी जी के साथ कार्य करने का समय आ चुका है। बहरहाल, घटनाक्रम इतनी तीव्रता से आगे बढ़ता चला गया कि लोग एक के बाद एक क्रमशः बदलते परिदृश्यों में उलझकर रह गए। यह सोचकर लोग हैरत में थे कि 11 मार्च को मादी जी ने खट्टर की प्रशंसा की, 12 को दोपहर तक वे हटा दिए गए और शाम होते-होते उनके बेहद करीबी माने जाने वाले और कभी उनके मातहत रहने वाले राजनेता नायब सिंह सैनी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बना दिए गए। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में भाजपा का बड़ा ओबीसी चेहरा हैं। फिलहाल वे भाजपा से लोकसभा के सदस्य हैं, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सैनी राजनीति में आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे। आरएसएस में रहते हुए ही उनकी मुलाकात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई थी, जिसके कुछ समय बाद ही वे भाजपा में शामिल हो गए थे।

भतीजे चिराग की राह में अड़ंगा क्यों बने चाचा पारस?

आलोक कुमार

राजनीति के बदलते मौसम के विशेषज्ञ माने जाने वाले रामविलास पासवान आठ अक्टूबर 2020 को दुनिया छोड़ कर चले गए मगर उनकी विरासत की लड़ाई आज भी बिहार की राजनीति पर हावी है। यह लड़ाई सत्तारूढ एनडीए के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस ने भाजपा नेताओं की पहल पर भतीजे चिराग पासवान के हाथ जा रही राजनीतिक विरासत में आखिरी वक्त पर अड़ंगा डाल दिया है। इससे लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर एनडीए के लिए बिहार में लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा का काम मुश्किल में फंस गया है।

एनडीए की घमासान से फायदा उठाने की चाह में इंडिया गठबंधन ने भी सीटों के बंटवारे की घोषणा फिलहाल टाल दी है। इंडिया गठबंधन को मुकेश सहनी का भी इंतजार है, जो एनडीए से टिकट नहीं मिलने की सूरत में वापस तेजस्वी के पाले में आ सकते हैं। ऐसे में चिराग के चाचा पारस के मुंह से फूटे बगावती सुर ने इंडिया गठबंधन की आस बढ़ा दी है। नाजुक हालात में दोनों ओर से सीट बंटवारे की घोषणा का काम अब अगले दो चार दिनों तक के लिए टल गया है। जबकि उम्मीद थी कि गुरुवार को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही बिहार में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों की घोषणा सहजता से हो जायेगी। आखिरी वक्त में रामविलास पासवान की विरासत का विवाद सुलझाने के लिए कई राउंड की बैठकों के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस निर्णय पर पहुंचे थे कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोकजनशक्ति पार्टी को एनडीए में शामिल किया जाए और सीटों का समझौता चिराग गुट तक ही सीमित रखा जाए। बदले हालात में चाचा पशुपतिनाथ पारस को फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल तो रखा जाए मगर आगे राजनीतिक वनवास के लिए मना लिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक पारस को भविष्य में किसी राज्य का गवर्नर बनाए जाने की बात थी। साथ ही एक अन्य भतीजे और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज को लोकसभा की बजाय राज्य विधानसभा की राजनीति में एडजस्ट करने की तैयारी थी। इसके लिए उनको नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के हालिया विस्तार में शामिल किया जाना था। मगर ऐन मौके पर चाचा पशुपतिनाथ पारस के बिफर जाने से सब गड्डमड हो गया। पारस ने पटना जाकर प्रिंस को मंत्रिमंडल में शामिल होने से रोक लिया और हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी होने का दावा ठोक दिया। हाजीपुर सीट परिवारिक विरासत पर दावेदारी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सीट से राम विलास पासवान चुनाव लड़ते थे। चिराग पासवान फिलहाल जमुई से सांसद हैं।

परिवारिक विरासत की लड़ाई में केंद्रीय मंत्री पारस को नीतीश कुमार ने एनडीए में अपनी हैसियत बढ़ाने की मंशा से बढ़ावा दिया था। खास परिस्थिति में यह सुनिश्चित किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से शामिल करें। यह काम नीतीश विरोधी चिराग पासवान को राजनीति में नौसिखिया होने का अहसास दिलाने के लिए भी किया गया था। खास ऑपरेशन के तहत अक्टूबर 2021 में लोकजनशक्ति पार्टी में बड़ी बगावत करवाई गई। इसमें तब नीतीश कुमार के सिपहसालार रहे ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन की खास भूमिका थी। जो खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से परेशान चल रहे थे। चाचा पारस के नेतृत्व में पार्टी के सभी पांच सांसदों के अलग गुट बनाने से खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान भौंचक रह गए। वे जैसे तैसे सम्हल पाए। मगर जबतक सम्हलते तब तक लोकजनशक्ति पार्टी के एनडीए में शामिल हुए धड़े के नेता के तौर पर चाचा पशुपतिनाथ पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई जा चुकी थी।

दरअसल नीतीश कुमार की शिकायत थी कि बीजेपी चिराग पासवान का इस्तेमाल एनडीए में उनकी हैसियत कम करने की साजिश के तहत कर रही है। चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की बात नहीं बनने की वजह से एनडीए से अलग होकर लड़े थे। लिहाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि बुलंद रखने के लिए बीजेपी को चिराग से दूरी बनाए रखने के लिए मना लिया गया था।

चिराग पासवान के अलावा नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता रहे आरपीएन सिंह को राज्यसभा तक में नहीं भेजा गया। बाद में नीतीश कुमार ही उन्नीस महीने के लिए एनडीए छोड़ गए। तब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह के भविष्य को लेकर भी मुश्किल पैदा हुई थी मगर शीर्ष बीजेपी नेताओं ने बड़ी सूझबूझ से हल निकाला था। नीतीश के उलटने पलटने का शिकार होने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल रहे। अब जब घटे राजनीतिक रसूख के साथ नीतीश कुमार फिर एनडीए में आए हैं, तब केंद्रीय मंत्री पारस जैसे कारिंदों की हैसियत भी कम हो जाने का आकलन किया जा रहा था।

मगर केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस के बागी सुर ने बिहार में एनडीए की सुलझती गुत्थी को नए सिरे से उलझा दिया है। कई राउंड की बैठकों के बाद बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में न सिर्फ उन्होंने भतीजे प्रिंस राज को शामिल होने से रोक दिया बल्कि बड़े भतीजे चिराग पासवान की उड़ान की चाह पर फिर ग्रहण लगा दिया है। उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट छोड़ने से साफ इंकार कर दिया है।

राजस्थान में कांग्रेस ने उम्मीदवार तो दमदार उतारे हैं, देखना होगा कि परिणाम क्या रहता है?

रमेश सर्राफ धमोरा

राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पिछले दो बार के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर चुनाव हारने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इसीलिए अब तक घोषित 10 प्रत्याशियों में से किसी भी पुराने प्रत्याशी को रिपीट नहीं किया गया है। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। यदि यह सभी नेता भी चुनाव मैदान में उतरते तो कांग्रेस बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता। हालांकि अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को इस बार भी लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। मगर उनका क्षेत्र बदलकर जोधपुर के स्थान पर जालौर-सिरोही कर दिया गया है। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए चूरू के सांसद राहुल कस्वां को भी चूरू से प्रत्याशी बना दिया है। इसके साथ ही उदयपुर सीट पर आईएएस से इस्तीफा देने वाले ताराचंद मीणा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की सूची में बीकानेर सुरक्षित सीट से गोविंदराम मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। गोविंदराम मेघवाल पिछला विधानसभा चुनाव खाजूवाला क्षेत्र से हार गए थे। वह पिछली गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री व पूर्व में भाजपा से भी विधायक रह चुके हैं। पिछली बार बीकानेर से मदन गोपाल मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं 2014 में पूर्व सांसद शंकर पन्नू को प्रत्याशी बनाया गया था। चूरू संसदीय सीट पर दो बार भाजपा से सांसद बने राहुल कस्वां को प्रत्याशी बनाया गया है। राहुल कस्वां के पिता रामसिंह कस्वां चूरू से चार बार सांसद रह चुके हैं। जिले में इन्होंने ही सबसे पहले भाजपा का खाता खोला था। मगर राहुल कस्वां का टिकट काट देने से वह कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। चूरू से पिछली बार रफीक मंडेलिया व 2014 में प्रताप पूनिया को प्रत्याशी बनाया गया था। झुंझुनू सीट से विधायक बृजेंद्र ओला को प्रत्याशी बनाया गया है। चार बार के विधायक बृजेंद्र वाला गहलोत सरकार में परिवहन राज्य मंत्री थे। उनके पिता शीशराम ओला झुंझुनू से पांच बार सांसद, नौ बार विधायक, केंद्र व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। झुंझुनू से पिछली बार सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार को व 2014 में बृजेंद्र ओला की पत्नी राजबाला ओला को प्रत्याशी बनाया गया था। यादव मतदाताओं की बहुलता वाली अलवर सीट पर मुंडावर विधायक ललित यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। ललित यादव ने पिछला विधानसभा चुनाव 34526 मतों से जीता था। अलवर से पिछले दो बार कांग्रेस से भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़कर बड़े अंतर से पराजित हुए थे। भरतपुर सुरक्षित सीट से संजना जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि पिछली बार अभिजीत कुमार जाटव व 2014 में डॉक्टर सुरेश जाटव प्रत्याशी थे। इस बार की प्रत्याशी संजना जाटव पिछला विधानसभा चुनाव कठूमर सीट से मात्र 409 मतों से हार गई थी। संजना जाटव अभी अलवर जिला परिषद की सदस्य हैं तथा मात्र 26 साल की उम्र से ही उसे लगातार कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल रही है। संजना जाटव कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के अभियानों से जुड़ी हुई हैं। इसी के चलते उन्हें टिकट मिला है। टोंक-सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस ने देवली विधायक हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। जबकि पिछली बार उनके भाई नमोनारायण मीणा व उससे पहले क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन चुनाव लड़ चुके हैं। यहां से सचिन पायलट के चुनाव लड़ने की चर्चा थी। मगर उन्होंने अपने विश्वासपात्र हरीश मीणा को मैदान में उतार दिया है। हरीश मीणा 2014 में भाजपा से सांसद व 2018 तथा 2023 में कांग्रेस से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। वह पूर्व में राजस्थान पुलिस के डीजीपी रह चुके हैं।

होलिका दहन पर भद्रा की छाया, मिलेगा सिर्फ एक घंटा 20 मिनट

रंगों का त्योहार होली हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन बाद मनाया जाता है। होली के एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है। इस बार होलिका दहन 24 मार्च 2024 को है फिर उसके एक दिन बाद 25 मार्च को होली खेली जाएगी। हिंदू धर्म में होली का त्योहार विशेष महत्व रखता है। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होती है। जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। होली के दिन सभी मिलकर एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाते हैं। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन के लिए एक घंटा 20 मिनट का ही समय रहेगा। इसकी वजह इस दिन उस दिन भद्रा प्रात: 9.55 से आरंभ होकर मध्य रात्रि 11.13 तक भूमि लोक की रहेगी। जो की सर्वथा त्याज्य है। अत: होलिका दहन भद्रा के पश्चात मध्य रात्रि 11.13 से मध्य रात्रि 12.33 के मध्य होगा। होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 07.34 बजे से अगले दिन सुबह 06.19 बजे तक है। वहीं रवि योग रवि योग सुबह 06.20 बजे से सुबह 07.34 बजे तक है।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि होली के एक दिन पहले पूर्णिमा की तिथि में होलिका दहन किया जाता है। वहीं पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च सुबह 8:13 मिनट से लेकर अगले दिन 25 मार्च सुबह 11:44 मिनट तक रहने वाली है। दिन भर उदय के कारण 24 मार्च को ही पूर्णिमा तिथि मान्य रहेगी। इस वर्ष होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। जबकि इसके एक दिन पहले 24 मार्च को होलिका दहन है। होली उत्सव से आठ दिन पहले होलाष्टक लगेगा। होलाष्टक 17 मार्च से लग जाएगा।

होलिका दहन पर भद्रा का साया

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि पंचांग के अनुसार 24 मार्च को होलिका दहन के लिए लोगों के पास केवल 1 घंटा 20 मिनट का समय रहेगा। इसकी वजह इस दिन उस दिन भद्रा प्रात: 9:55 से आरंभ होकर मध्य रात्रि 11:13 तक भूमि लोक की रहेगी। जो की सर्वथा त्याज्य है। अत: होलिका दहन भद्रा के पश्चात मध्य रात्रि 11.13 से मध्य रात्रि 12.33 के मध्य होगा। उस दिन भद्रा की पूंछ शाम 06.33 बजे से शाम 07.53 बजे तक है, वहीं भद्रा का मुख शाम 07.53 बजे से रात 10.06 बजे तक है। भद्रा योग रहेगा। भद्रा को अशुभ माना जाता है।

यथा भद्रायां हे न कर्तव्ये श्रावणी (रक्षाबंधन) फाल्गुनी (होलिकादहन) तथा।
श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्राम दहति फाल्गुनी॥
(मुहर्त्तचिंतामणि)

भद्रा समाप्ति के बाद होलिका दहन मुहूर्त

साल 2024 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा के पश्चात मध्य रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 12:33 तक है। होलिका दहन के लिए 1 घंटा 20 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 07:34 बजे से अगले दिन सुबह 06:19 बजे तक है। वहीं रवि योग रवि योग सुबह 06:20 बजे से सुबह 07:34 बजे तक है।

नहीं होते भद्रा में शुभ कार्य

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि पुराणों के अनुसार भद्रा सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन है। भद्रा क्रोधी स्वभाव की मानी गई हैं। उनके स्वभाव को नियंत्रित करने भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना य ा पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। पंचांग के 5 प्रमुख अंग तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण होते हैं। करण की संख्या 11 होती है। ये चर-अचर में बांटे गए हैं। इन 11 करणों में 7वें करण विष्टि का नाम ही भद्रा है। मान्यता है कि ये तीनों लोक में भ्रमण करती हैं, जब मृत्यु लोक में होती हैं, तो अनिष्ट करती हैं। भद्रा योग कर्क, सिंह, कुंभ व मीन राशि में चंद्रमा के विचरण पर भद्रा विष्टिकरण का योग होता है, तब भद्रा पृथ्वीलोक में रहती है।

होलिका दहन विधि

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि होलिका दहन का तैयारी कई दिनों पहले से होने लगती हैं। होलिका दहन वाले स्थान पर लकड़ियां, उपले और अन्य जलाने वाली चीजों को एकत्रित किया जाता है। इसके बाद होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर विधिवत रूप से पूजन करते हुए होलिका में आग लगाई जाती है। फिर होलिका की परिक्रमा करते हुए पूजा सामग्री को होलिका में डाला जाता है।

होली की पौराणिक कथा

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि होली का त्योहार मुख्य रूप से विष्णु भक्त प्रह्लाद से जुड़ी है। भक्त प्रह्लाद का जन्म राक्षस परिवार में हुआ था, परन्तु वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को अनेकों प्रकार के कष्ट दिए। हिरण्यकश्यप ने कई बार भक्त प्रह्लाद को मारने की कोशिश की लेकिन हर बार नकामी ही मिली। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को भक्त प्रह्लाद को मारने की जिम्मा सौपा। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। उनकी बुआ होलिका जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका भक्त प्रह्लाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर आग में बैठ गई। भक्त प्रह्लाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई लेकिन भक्त प्रह्लाद को कुछ नहीं हुआ। इसके प्रथा के चलते हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है।

– डा. **अनीष व्यास**

जानिए कब से चैत्र नवरात्रि शुरु हो रही है? देखें तारीख और शुभ योग

दिव्यांशी भदौरिया

इस साल 2024 की चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो रहे हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का पहले दिन दो शुभ योग बन रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कब से शुरु हो रहे चैत्र नवरात्रि इसके साथ ही जाने प्रमुख तिथियां। 9 दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरुपों की उपासना की जाती है।

चैत्र नवरात्रि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि है। मां दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का यह पर्व देशभर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरुपों की उपासना की जाती है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि है, लेकिन मुख्य रुप से साल की दो नवरात्रि का पर्व आम इंसान के द्वारा मनाया जाता है। वहीं 2 गुप्त नवरात्रि को साधु-संत और तंत्रिक के द्वारा मनाया जाता है। साल की दो नवरात्रि जिन्हें हम मनाते हैं एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरी चैत्र नवरात्रि। अब चैत्र नवरात्रि आने का समय आ गाया है।

चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो इस बार 8 अप्रैल को देर रात 11 बजकर 50 मिनट पर लगेगी और अगले दिन से यानी 9 अप्रैल को रात के समय 8 बजकर 30 मिनट पर समाप्त हो जाएगी। वहीं चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा। 9 अप्रैल को घटस्थापना का मुहूर्त सुबह 6 बजकर 3 मिनट से 10 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। दरअसल, इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस योग के दौरान की गई पूजा व्यक्ति को सुख और समृद्धि दिलाएगा।

चैत्र नवरात्रि की तिथियां

- चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल 2024- मां शैलपुत्री की पूजा
- चैत्र नवरात्रि द्वितीया तिथि व्रत 10 अप्रैल 2024 - मां ब्रह्मचारिणी की पूजा
- चैत्र नवरात्रि तृतीया तिथि व्रत 11 अप्रैल 2024 - मां चंद्रघंटा की पूजा
- चैत्र नवरात्रि चतुर्थी तिथि व्रत 12 अप्रैल 2024 - मां कुष्माण्डा की पूजा
- चैत्र नवरात्रि पंचमी तिथि व्रत 13 अप्रैल 2024 - मां स्कंदमाता की पूजा
- चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि व्रत 14 अप्रैल 2024 - मां कात्यायनी की पूजा
- चैत्र नवरात्रि सप्तमी तिथि व्रत 15 अप्रैल 2024 - मां कालरात्री की पूजा
- चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि व्रत 16 अप्रैल 2024 - मां महागौरी की पूजा, अष्टमी पूजन
- चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि व्रत 17 अप्रैल 2024 - मां सिद्धिदात्री की पूजा, नवमी पूजन

जानें कब है रंगभरी एकादशी? देखें शुभ मुहूर्त और इसका महत्व

फाल्गुन माह को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय महीना माना जाता है। फाल्गुन माह में कई पर्व आते है जो जीवन में उत्साह लेकर आते है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती है। इन्हीं में से एक फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी जिसे रंगभरी एकादशी के नाम से जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। आइए आपको बताते हैं फाल्गुन माह में कब मनाई जाएगी रंगभरी एकादशी, क्या है इसका शुभ मुहूर्त और महत्व।

रंगभरी एकादशी कब है?

फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की रंगभरी एकादशी का शुभारंभ 19 मार्च, दिन मंगलवार को रात 12 बजकर 22 मिनट पर होगा। वहीं, इसका समापन 20 मार्च, दिन बुधवार को रात 2 बजकर 23 मिनट पर होगा। दरअसल, उदया तिथि के अनुसार, रंगभरी एकादशी का व्रत 20 मार्च को रखा जाएगा।

रंगभरी एकादशी का शुभ मुहूर्त

ज्योतिष के अनुसार, रंगभरी एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। ऐसे में पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 25 मिनट से आरंभ होगा। इसका समापन सुबह 9 बजकर 27 मिनट पर होगा। वहीं पूजा करने का समय कुल 3 मिनट तक रहेगा। इस दौरान पूजा करना शुभ और लाभदायक रहेगा।

रंगभरी एकादशी का महत्व

इस एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने होली खेली थी। इसके साथ ही यह माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती का गौना हुआ था। ऐसे में इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए।

रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को गुलाल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और दांपत्य जीवन में मधुरता आती है।

पिछले कुछ समय से पूरे भारत में अयोध्या स्थित राम मंदिर की चर्चा चल रही है। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद एक फेमस धार्मिक स्थल बन गया है। अयोध्या स्थित राम मंदिर कई चीजों के लिए फेमस है। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में कई ऐसे

माता सीता को मुंह दिखाई में मिला था अयोध्या का यह महल, श्रीकृष्ण से भी जुड़ा है इसका इतिहास

धार्मिक स्थल, भवन, इमारत, मंदिर और महल मौजूद हैं। जो किसी न किसी रूप में रामायण काल से जुड़ी है। आपको बता दें कि प्रभु राम की नगरी आयोध्या में एक ऐसा महल भी है, जिसके बारे में बताया जाता है यह माता सीता को मुंह दिखाई में मिला था। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस महल से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताने जा रहे हैं।

कनक महल

बताया जाता है कि माता सीता को मुंह दिखाई में जो महल मिला था, उसका नाम %कनक भवन% था। जब प्रभु श्रीराम जनक नंदनी से विवाह के बाद अयोध्या पहुंचे थे, तो महारानी कैकेयी ने मां सीता को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप कनक महल दिया था। मान्यता के मुताबिक देवी सीता और प्रभु श्रीराम का यह कनक महल निजी महल हुआ करते थे। हर दिन हजारों की संख्या में इस महल को देखने के लिए लोग अयोध्या पहुंचते हैं। वर्तमान समय में कनक महल अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है।

विश्वकर्मा ने बनाया था कनक महल

कनक महल के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन महारानी कैकेयी ने अपने सपने में एक दिव्य महल देखा। अगले दिन महारानी ने राजा दशरथ से अपने स्वप्न के बारे में बताया और ठीक वैसा ही महल बनवाने की इच्छा जताई। महारानी कैकेयी की महल बनवाने की इच्छा के बाद महाराजा दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक भव्य और सुंदर महल का निर्माण करवाया था। वहीं प्रभु राम की शादी के बाद माता सीता के अयोध्या आने पर महारानी कैकेयी ने उन्हें मुंह दिखाई में कनक महल दिया था।

कनक महल की पौराणिक कथा

कनक महल की पौराणिक कथा बहुत दिलचस्प है। लोक मान्यता के अनुसार, द्वापर युग में प्रभु श्रीकृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी समेत अयोध्या पहुंचे, तब कनक भवन खंडहर बन चुका था। लेकिन फिर भी भगवान श्रीकृष्ण को टीले पर आनंद आता था। ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण ने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह कनक महल है। तब श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से श्री सीताराम की मूर्तियों को प्रकट कर स्थापित किया था।

महल का जीर्णोद्धार

कनक महल में स्थापित शिलालेखों से जानकारी मिलती है, इस महल का कई बार जीर्णोद्धार किया जा चुका है। बताया जाता है कि सबसे पहले श्रीराम के पुत्र कुश ने कनक महल का जीर्णोद्धार कराया था। साथ ही उन्होंने महल में भगवान श्रीराम और मां सीता की मूर्तियां स्थापित करवाई थीं। वहीं कुश के बाद श्रीकृष्ण ने इस महल का पुनर्निमाण करवाया था। इसके अलावा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी इस महल का पुनर्निर्माण किया था। बताया जाता है कि वर्तमान समय में महल का जो स्वरूप मौजूद है, उसको राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु द्वारा बनवाया गया है।

बेहद खास हैं कनक भवन की मूर्तियां

कनक महल को मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्रीराम, मां सीता, श्रीलक्ष्मण और भरत-शत्रुघ्न विराजमान हैं। अयोध्या का यह इकलौता ऐसा महल है, जहां पर प्रभु श्रीराम माता सीता के साथ अपने भाइयों के साथ विराजमान हैं।

इस समय घूमने जाएं

वैसे तो आप कभी भी कनक महल घूमने के लिए जा सकते हैं। गर्मियों में सुबह 08 बजे से लेकर रात के 09 बजे तक घूम सकते हैं। वहीं सर्दियों में सुबह 09 बजे से रात 08 बजे के बीच घूमने के लिए जा सकते हैं।

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान, बच्चे पर नहीं पड़ेगा बुरा असर

चंद्र ग्रहण का दिन सनातन धर्म में बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण के दिन ज्यादा से ज्यादा पूजा-पाठ और पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में कई सारे नियम बताए गए हैं।

वहीं, इस दिन गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं -

चंद्र ग्रहण का सही समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च, 2024 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। बता दें, चंद्र ग्रहण की अवधि 25 मार्च सुबह 10 बजकर 24 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 01 मिनट तक रहेगी। ऐसे में लोगों को इस साल होली और चंद्र ग्रहण एक ही दिन हैं जिसके चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। खासतौर पर गर्भवती महिलाएं इस दिन विशेष सावधानी बरतें। कुल 4 घंटे और 36 मिनट तक सतर्क रहना है। साथ ही वैदिक मंत्रों का जाप करते रहना है। वहीं, इस दिन होली का पर्व भी मनाया जाएगा।

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान

- चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसकी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है।
- ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली वस्तु जैसे - कैंची, चाकू आदि के इस्तेमाल से बचना चाहिए।
- इस समय कुछ भी खाने से बचना चाहिए।
- अपने घर की खिड़कियों को मोटे पर्दों से ढक दें, ताकि ग्रहण की नकारात्मक किरणें घर में प्रवेश न करें।
- ग्रहण से पहले बने हुए भोजन का प्रयोग न करें।
- ग्रहण समाप्त होने के बाद पानी में गंगाजल मिलाकर पवित्र स्नान करें।
- इस दौरान गर्भवती महिलाएं मन में भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान करती रहें।
- ग्रहण के दौरान सोने से परहेज करें।
- सभी खाने और पीने की चीजों में तुलसी पत्र डाल दें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

21 तक का समय, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को 21 मार्च तक सभी चुनावी बांड विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने चुनावी बांड मामले में अपने फैसले में बैंक से बांड के सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और उसे अगले आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च को चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से डिजीटल रूप में प्राप्त डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रू. 6,986.5 करोड़ की अधिकतम धनराशि प्राप्त हुई। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (रू. 1,397 करोड़), कांग्रेस (रू. 1,334 करोड़) की अधिकतम धनराशि प्राप्त हुई।

सत्येंद्र जैन को झटका, जल्द से जल्द सरेंडर कीजिए

नईदिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उच्चतम न्यायालय ने सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी और तुरंत सरेंडर करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन से तत्काल आत्मसमर्पण करने को कहा। जैन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। न्यायालय ने जैन को आत्मसमर्पण करने के लिए एक हफ्ते का वक्त देने के उनके वकील के मौखिक अनुरोध को ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत ने जैन की नियमित जमानत याचिका पर 17 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और बार-बार जमानत की अवधि बढ़ायी जाती रही।

पूरा देश चाहता है कि राहुल अगला पीएम बनें : राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सोमवार को कांग्रेस के राहुल गांधी को बड़ा नेता बताया और दावा किया कि देश उन्हें अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। यह टिप्पणी विपक्षी दल इंडिया गुट द्वारा राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के बाद मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली में चुनावी बिगुल बजाने के एक दिन बाद आई है। रैली को राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा, राहुल गांधी देश के एक प्रमुख नेता हैं। देश उन्हें अगले प्रधान मंत्री के रूप में देखता है। राहुल गांधी एक अच्छे इंसान और नेता हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं। हम सभी उनके साथ खड़े हैं। आगे शिवाजी पार्क रैली पर बोलते हुए राउत ने कहा कि विपक्ष अनदेखी ताकतों के खिलाफ लड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कल, हमने भारत गठबंधन के लिए एक रैली का आयोजन किया।

लालू की बेटी रोहिणी सारण लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी

पटना। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपना चुनावी डेब्यू करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह सारण लोकसभा क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, सूत्रों ने कहा। पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया चैनलों के जरिए इस घटनाक्रम के संकेत भी दिए हैं। सारण सीट से लालू परिवार के सदस्य लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे हैं। फिलहाल लालू के तीन बच्चे सक्रिय रूप से राजनीति में हैं। इनमें उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ-साथ उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि रोहिणी ही वह व्यक्ति थीं, जिन्होंने दिसंबर 2022 में सिंगापुर स्थित एक अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी के दौरान अपने पिता को उदारतापूर्वक अपनी एक किडनी दान की थी। सूत्रों के मुताबिक, रविवार (17 मार्च) को हुई राजद की बैठक के दौरान राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने सारण सीट के लिए रोहिणी के नाम का प्रस्ताव रखा।

कर्नाटक में जल संकट, केंद्र का मदद से इनकार: कांग्रेस

नईदिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर्नाटक के प्रस्तावित दौरे का उल्लेख करते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि प्रदेश गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के शिवमोगा में हैं। हमें उम्मीद है कि वह अपने संबोधन में राज्य के कुछ प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा, कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों में गंभीर सूखे की स्थिति के कारण राज्य गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। राज्य की 236 तालुकाओं में से 223 सूखे की स्थिति का सामना कर रही हैं। राज्य सरकार ने मोदी सरकार से सूखा राहत के लिए 18,172 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। रमेश ने सवाल किया कि मोदी सरकार ने अब तक कर्नाटक के लोगों की मदद करने से इनकार क्यों किया है? उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार कर्नाटक के मनरेगा मजदूरों को उनकी मजदूरी कब देगी?

शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान पर प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर पलटवार

'शक्ति' के लिए लगा दूंगा जान की बाजी : मोदी

हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन पर मुंबई की रैली से 'शक्ति' के विनाश का बिगूल फूंकने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि उनके लिए हर मां-बेटी 'शक्ति' का स्वरूप है और वह उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ाई 'शक्ति के विनाशकों' और 'शक्ति के उपासकों' के बीच है और चार जून को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन 'शक्ति' का विनाश करने वाला है और किसे 'शक्ति' का आशीर्वाद प्राप्त है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में कहा था, ''मुंबई से आज 'हिंदुस्तान की आवाज़' निकली है-देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति, 'इंडिया' की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती।'' उन्होंने कहा, ''नरेन्द्र मोदी एक नकारात्मक शक्ति का मुखौटा हैं। वही शक्ति, जिसने हिंदुस्तान की संस्थाओं को गुलाम बना लिया है, वही शक्ति, जो भारत के किसान-मज़दूर, युवा-महिला, गरीब और छोटे उद्योगों को निचोड़ कर सब कुछ अपने चंद अरबपति मित्रों पर लुटा देना चाहती है, वही शक्ति, जो देश में आज भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। अब इस शक्ति को करारा जवाब देने का वक्त है।'' इस रैली में विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल कनक्लूसिव अलायंस' यानी 'इंडिया' के घटक दल के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे।

राहुल की इसी टिप्पणी को हथियार बना प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की रैली में विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। रैली में पहुंची महिलाओं को संबोधित करते हुए मोदी ने उन्हें शक्ति स्वरूपा कहकर संबोधित किया और कहा कि वे शक्ति का रूप धारण कर उन्हें आशीर्वाद देने आई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद रविवार को मुंबई में 'इंडी' अलायंस की 'सबसे महत्वपूर्ण' रैली थी और उस रैली में उन्होंने अपना घोषणापत्र जाहिर किया। मोदी ने कहा, ''उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई 'शक्ति' के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां-बेटी शक्ति का रूप है। मैं आपकी शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब बहन बेटियों का पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क मेंज 'इंडी'

अलायंस ने अपने घोषणापत्र में शक्ति को खत्म करने के लिए कहा हैज् मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं शक्ति स्वरूपा माताओं-बहनों के लिए जान की बाजी लगा दूंगाज् जीवन खपा दूंगा।''

उन्होंने सवालिया अंदाज में जनसूह से पूछा कि क्या भारत की धरती पर कोई 'शक्ति' के विनाश की बात कर सकता है? और क्या 'शक्ति' का विनाश हमें मंजूर है? मोदी ने कहा कि पूरा हिन्दुस्तान 'शक्ति' की आराधना करता है और उनकी सरकार ने तो चंद्रयान की सफलता को भी 'शिव शक्ति' का नाम दिया। उन्होंने फिर सवालिया लहजे में कहा, ''और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगूल फूंक रहे हैं। मताताएं-बहनें, शक्ति स्वरूपा आप हैं। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने का मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मोदी ने कहा, ''इंडी अलांयस ने घोषणापत्र जाहिर किया है। लड़ाई एक तरफ शक्ति का विनाश करने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला चार जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति का आशीर्वाद हासिल करता है।''

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव प्रारंभ हो चुका है और 13 मई को तेलंगाना के लोग नया इतिहास रचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 13 मई को तेलंगाना में होने वाला मतदान 'विकसित भारत' के लिए होगा और जब भारत विकसित होगा तो तेलंगाना भी विकसित होगा।

प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल में और तेजी से काम करने के लिए अभी से मुस्तैद

लोकसभा चुनाव के परिणाम वैसे तो 4 जून को आयेंगे लेकिन देश की जनता जिस तरह अबकी बार 400 पार का नारा लगा रही है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णत: आश्वस्त हैं कि देश की जनता सेवा के लिए उन्हें तीसरा कार्यकाल सौंपने जा रही है। इसीलिए मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में लिये जाने वाले बड़े फैसलों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। उन्होंने हाल ही में अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक में और चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद बुलाई गयी मंत्रिमंडल की बैठक में अपने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद अपने काम सुचारू रूप से करते रहें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से नयी सरकार के पहले 100 दिन और अगले पांच साल के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री ने रविवार सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्रियों से अपने-अपने मंत्रालयों के सचिवों और अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर इस बारे में चर्चा करने के लिए कहा कि नयी सरकार के पहले 100 दिन और अगले पांच साल के एजेंडे को बेहतर ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है। हम आपको याद दिला दें कि तीन मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ''विकसित भारत : 2047'' के लिए दृष्टि पत्र और अगले पांच वर्ष के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना पर मंथन किया गया था। उस बैठक में, मई में नयी सरकार के गठन के बाद तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के लिए 100 दिवसीय एजेंडे और उसके शीघ्र क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई थी। हम आपको बता दें कि ''विकसित भारत'' के लिए 'रोडमैप' दो साल से अधिक की गहन तैयारी का परिणाम है। इसमें सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, उद्योग संगठनों, नागरिक संस्थाओं, वैज्ञानिक संगठनों के साथ व्यापक परामर्श तथा युवाओं के सुझावों को समाहित करते हुए ''सरकार का समग्र'' दृष्टिकोण शामिल है। मोदी ने विपक्ष का नाम लिये बिना कहा कि वह (मोदी) ''राष्ट्र प्रथम'' से प्रेरित हैं जबकि ''वे (विपक्ष) परिवार प्रथम'' की सोच पर चलते हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हुआ मुंबई

एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच चल रहे शब्दवाण

मुंबई। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रचार की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुंबई भी राजनीतिक अखाड़ा बन गया जब तारीखों के ऐलान के बाद इंडिया गढबंधन बनाम एनडीए के बीच जबरदस्त वार-पलटवार का दौरा देखा गया। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में ही खत्म की है। कांग्रेस नेता का अंतिम दिन प्रतीकात्मकता से भरा हुआ था, जो तत्कालीन बॉम्बे में महात्मा गांधी के लंबे समय के मुख्यालय मणि भवन से शुरू हुआ और डॉ. बीआर अंबेडकर के दाह संस्कार स्थल चैत्य भूमि पर समाप्त हुआ।

राहुल चैत्य भूमि के सामने विनायक दामोदर स्मारक पर नहीं गए, लेकिन भाजपा द्वारा राहुल के सहयोगी उद्धव ठाकरे को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश के बाद बगल के बाल ठाकरे स्मारक पर गए। जबकि भाजपा ने सावरकर स्मारक नहीं जाने के राहुल के फैसले को गलत ठहराया और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिव सेना (यूबीटी) पर हमला करते हुए हिंदुत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया, यह दिन एक बार के लिए इंडिया गठबंधन के लिए था, जब उसके सहयोगी उस गठबंधन के इर्द-गिर्द एकजुट हो रहे थे जो तेजी से आगे बढ़ने की राह पर बढ़ रहा है। इससे इस धारणा का भी खंडन किया जा सकेगा कि कांग्रेस ने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भारतीय सहयोगियों को दूर रखा।

रविवार शाम को शिवाजी पार्क में आयोजित रैली में मंच पर राहुल और प्रियंका गांधी वाद्रा के अलावा अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ सेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति थी, जो यात्रा के औपचारिक समापन को चिह्नित करने के लिए शिवसेना के लिए बहुत महत्व रखता है। राज्य में कांग्रेस के अन्य मुख्य सहयोगी एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के साथ-साथ उसके सहयोगी

डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी और राजद भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्र भेजकर अपना समर्थन जताया।

एक के बाद एक दिए गय भाषण में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा पर तानाशाही, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लड़ने के लिए एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम विकसित करने का संकल्प लिया। भाजपा ध्यान दे रही थी, यह इस बात से स्पष्ट था कि उसने रैली पर कितना ध्यान केंद्रित किया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने दिवंगत बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो क्लिप पोस्ट किया, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि शिव सेना को कांग्रेस के साथ जाना होगा, तो मैं अपना संगठन बंद कर दूंगा। बावनकुले ने कहा, हम उद्धव ठाकरे को कुछ भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सिर्फ याद दिला रहे हैं कि बाल ठाकरे ने कांग्रेस के साथ (उनके) अपवित्र गठबंधन के बारे में क्या कहा थाज् सेना (यूबीटी) ने सत्ता के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर 2019 में पहले ही अपनी हिंदुत्व विचारधारा से समझौता कर लिया है। अब, यह स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर अपने रुख से समझौता करने के लिए तैयार है। हालाँकि, इस हमले से बहुत कुछ होने की संभावना नहीं है, यह देखते हुए कि कांग्रेस-एनसीपी के साथ उद्धव का गठबंधन अब पूराना हो चुका है।

खेल
प्रमुख समाचार

आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किया खिताब पर कब्जा

नईदिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने अपना पहला डब्ल्यूपीएल खिताब जीता लिया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली सहित कई दिग्गज ने बधाई दी। तीन गेंद पहले जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा कर लिया। हारते-हारते जीत गए। 8 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत दर्ज की। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सोफी मोलिनेक्स को दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को मिला। श्रेयंका पाटिल को टूर्नामेंट की उभरती हुई खिलाड़ी चुना गया। आरसीबी ने फेयरप्ले अवॉर्ड भी जीता। श्रेयंका को पर्पल कैप दिया गया, जिसने टूर्नामेंट में 13 विकेट झटके। एलिसे पेरी को ऑरेंज कैप से नवाजा गया। दिल्ली कैपिटल्स अच्छी शुरुआत करने के बावजूद आरसीबी के स्पिनरों के सामने घुटने टेककर इस साल भी खिताब से चूक गयी।

पिछले साल टूर्नामेंट के पहले चरण में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में मुंबई इंडियंस से हार मिली थी। वहीं आरसीबी महिला टीम का यह पहला फाइनल था और उसने धीमी शुरुआत के बाद दबाव से निपटते हुए आखिर में जीत हासिल की। आरसीबी की गेंदबाजी के सामने दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजों के लचर प्रदर्शन से 18.3 ओवर में महज 113 रन पर सिमट गयी।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने धीमी शुरूआत की और कछुआ चाल से चलते हुए 19.3 ओवर में दो विकेट पर 115 रन बनाकर खिताब जीत लिया। उसकी बल्लेबाज टीम के पहले फाइनल में मैदान पर काफी दबाव में थीं लेकिन अंत में इससे निपटने में सफल रहीं। ऋचा घोष (नाबाद 17 रन, 14 गेंद, दो चौके) ने टीम के लिए विजयी चौका जड़ा। मंधाना ने 39 गेंद में 31 रन की धीमी पारी खेली और सोफी डिवाइन ने 27 गेंद में पांच चौके और एक छक्के से 32 रन का योगदान दिया। एलिसे पैरी 35 रन बनाकर नाबाद रहीं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 105 तो निफ्टी 35 अंक चढ़ा

नईदिल्ली। बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। निवेशक इस सप्ताह यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट को लेकर फैसले और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सतर्क रुख अपना रहे हैं। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज 104.99 अंक या 0.14 प्रतिशत की बढ़त लेकर 72,748.42 अंक पर बंद हुआ। दिन के कामकाज के दौरान यह 72,985.89 के हाईएस्ट और 72,314.16 के नीचले स्तर तक चला गया था। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 32.35 अंक या 0.15 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,055.70 अंक के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील ने 5 प्रतिशत से ज्यादा की छलांग लगाई। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति अन्य सबसे बड़े लाभ में रहे।

अदाणी ग्रुप के शेयरों में गिरावट, अमेरिकी जांच वजह

नईदिल्ली। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की मार को झेल रहे गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप के लिए एक और नयी मुसीबत खड़ी हो गई है। इस वजह से ग्रुप के शेयरों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल अमेरिका में प्रॉसिक्यूटर ने अदाणी ग्रुप को लेकर जांच का दायरा बढ़ा दिया है जिसका असर समूह के शेयरों पर देखने को मिल रहा है। देसी शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच आज गौतम अदाणी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अदाणी टोटल गैस के शेयर 3.30 प्रतिशत की कमजोरी पर कामकाज कर रहे थे जबकि एनडीटीवी के शेयर करीब एक फीसदी गिरकर 217 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। बता दें कि अमेरिका में प्रॉसिक्यूटर ने अपनी जांच का दायरा अदाणी ग्रुप तक बढ़ा दिया है जिसके चलते समूह की कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है।

अनुप इंजीनियरिंग के शेयरों ने भरा फर्राटा

नईदिल्ली। अनुप इंजीनियरिंग के शेयर सोमवार को इंट्रा-डे कारोबार में बीएसई पर 15 प्रतिशत बढ़कर 3,115 रुपये पर पहुंच गए। औद्योगिक उत्पाद कंपनी का शेयर 9 फरवरी को 52 सप्ताह के हाई लेवल 3,168 रुपये पर पहुंच गया था। बता दें कि अनुप इंजीनियरिंग के शेयरों में यह तेजी कंपनी के बोर्ड की तरफ से बोनस मुद्दे पर विचार करने के लिए बुधवार यानी 20 मार्च को बुलाई गई बैठक के मद्देनजर आई है। अप्रैल 2023 से अब तक वित्त वर्ष 2023-24 में अनूप इंजीनियरिंग के शेयर की कीमत दोगुनी से अधिक या 110 प्रतिशत बढ़ गई है। अनुप इंजीनियरिंग लिमिटेड हीट एक्सचेंजर्स, रिएक्टरों, दबाव वाहिकाओं की अपनी बड़ी प्रोडक्ट सीरीज के साथ तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल्स, एलएनजी, हाइड्रोजन, उर्वरक, रसायन / फार्मास्यूटिकल्स, बिजली, पानी, कागज और लुगदी और एयरोस्पेस सहित प्रक्रिया उद्योगों की विस्तृत सीरीज की पेशकश करती है।

नारायणमूर्ति ने पोते को गिफ्ट किए रू. 240 करोड़ के शेयर

नई दिल्ली। इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने अपने चार महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को 240 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर उपहार में दिए हैं। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी में एकाग्र रोहन मूर्ति की 15,00,000 शेयर या 0.04 प्रतिशत हिस्सेदारी है। पोते को शेयर दान में देने के बाद इन्फोसिस में नारायणमूर्ति की हिस्सेदारी 0.40 प्रतिशत से घटकर 0.36 प्रतिशत रह गई। उनके पास अब कंपनी के करीब 1.51 करोड़ शेयर हैं। फाइलिंग के अनुसार, यह लेनदेन ऑफ-मार्केट तरीके से किया गया। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति नवंबर में दादा-दादी बने जब उनके बेटे रोहन मूर्ति और पत्नी अपर्णा कृष्णन को एक बेटा हुआ। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और अक्षता मूर्ति की दो बेटियों के नाना-नानी भी हैं।

अर्थव्यवस्था : चीन का विकल्प बनने को तैयार है भारत

पीएस वोहरा

चीन के आर्थिक हालात अब उसके वश में नहीं लग रहे हैं, जिससे अब उसका वैश्विक रुतबा भी डावांडोल होता दिखने लगा है। गौरतलब है कि पिछले दो-तीन दशकों में चीन से ज्यादा तीव्र आर्थिक प्रगति किसी अन्य मुल्क ने नहीं की है। 1990 के दौर में वैश्विक जीडीपी में चीन का हिस्सा मात्र दो फीसदी हुआ करता था, जो 2021 तक लगभग 20 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया। लेकिन अब उसमें गिरावट का दौर शुरू हो गया है।

कुछ लोग इसका श्रेय कोरोना के बाद अमेरिका की तेजी से आर्थिक रिकवरी को देते हैं, तो बाकी विश्व की कुछ अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं, जिसमें भारत सबसे ऊपर है, के अलावा वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पोलैंड की अर्थव्यवस्थाओं को भी देना उचित समझते हैं। हालांकि, अमेरिका को इसका श्रेय देना तर्कसंगत इसलिए लगता है, क्योंकि वर्ष 2022-23 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 80 खरब डॉलर का विस्तार हुआ है, जिसके चलते उसका वर्तमान स्तर तकरीबन 1050 खरब डॉलर के बराबर है और इस आर्थिक वृद्धि में अमेरिका का हिस्सा 45 फीसदी रहा है। यह अपने आप में एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अमेरिकी बादशाहत को दर्शाता है। हालांकि भारत का वर्तमान वैश्विक जीडीपी में हिस्सा तकरीबन चार फीसदी के आसपास है, पर भारत के विशाल घरेलू बाजार के चलते उसकी लगातार बढ़ रही आर्थिक विकास दर के कारण सभी सहमत हैं कि आने वाले समय में भारत ही वैश्विक स्तर पर चीन की जगह लेगा। इन सब के बीच, चीन को अभी से हारा हुआ नहीं समझा जा सकता। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि चीन के वर्तमान

आर्थिक हालात के पीछे का मुख्य कारण अमेरिका से उसकी अनावश्यक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। वर्ष 2021 तक चीन, अमेरिकी जीडीपी के 76 फीसदी हिस्से को कवर भी कर चुका था, परंतु अब उसमें काफी कमी आ गई है। वर्तमान में चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के जीडीपी का 65 फीसदी ही है।

आने वाले समय में यह अंतर और भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका के हालात उसके नियंत्रण में हैं, जबकि चीन में कई वजहों से अब स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं। इसका एक प्रमुख कारण है, चीनी सरकार व प्रशासन का सदैव वैश्विक स्तर पर बहुत अहंकारी रवैया। दूसरा, चीन के घरेलू बाजार में उपभोग क्षमता का लगातार कम होना, क्योंकि पिछली दो पीढ़ियां जनसंख्या नियंत्रण के चलते परिवार में एक बच्चे के साथ ही जीवन- यापन कर रही हैं। तीसरा मुख्य कारण चीनी अर्थव्यवस्था में वित्तीय ऋण का लगातार बढ़ता बोझ और चौथा मुख्य कारण है, बड़ी तेजी से चीनी बाजार का वैश्विक निवेशकों में अपना विश्वास खोना। चीन में अभी वित्तीय ऋण जीडीपी का 300 फीसदी है। आगामी वर्ष में प्रस्तावित चार से पांच फीसदी की विकास दर को हासिल करने के चक्कर में इस ऋण की मात्रा आने वाले कुछ वर्षों में 500 फीसदी हो जाएगी। सबसे बड़ी गड़बड़ी चीन में यह रही है कि वित्तीय ऋण का सबसे अधिक हिस्सा वहां की रियल एस्टेट कंपनियों को लगातार मिलता रहा। चीन में वर्तमान समय में तकरीबन 100 से अधिक बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हैं। इनमें से प्रथम 50 कंपनियां तो वित्तीय ऋण के कारण आर्थिक संकट में हैं। प्रथम पांच कंपनियां तो बैंकों द्वारा दिवालिया घोषित हो चुकी हैं, जिन पर 266 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है। दरअसल, चीन में भी रियल एस्टेट की कृत्रिम आर्थिक प्रगति का बुलबुला कुछ वैसे ही फूटने के कगार पर है, जैसे अमेरिका में वर्ष 2008 में लेहमन ब्रदर्स के दिवालिया होने पर हुआ था। पिछले दिनों चीनी सरकार तथा विश्व विख्यात चीनी बिजनेस टाइकून व अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के साथ जिस तरह से चीनी सरकार का विवाद चर्चाओं में रहा, उसके चलते बड़े वैश्विक निवेशक अब चीन से दूरी बनाने लगे हैं। भारत अपनी लगातार बढ़ रही प्रति व्यक्ति उपभोग क्षमता के कारण उनकी पहली पसंद बन रहा है।

कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भरी हुंकार, कहा

भाजपा कार्यकर्ताओं में अद्भुत ऊर्जा और शक्ति

हर व्यक्ति को मिल रहा योजनाओं का लाभः देव

रायपुर. भारतीय जनता पार्टी के विधानसभास्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की श्रृंखला में सोमवार को सक्ती में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में हुंकार भरते हुए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में अद्भुत ऊर्जा और शक्ति है. प्रदेश की सभी 11 सीटों पर भाजपा का कमल खिलाने का संकल्प लेकर इस कार्यकर्ता सम्मेलन से हम सब लेकर जाएं. इस लोकसभा चुनाव में पूरे देश में भाजपा के पक्ष में सकारात्मक वातावरण दिखाई दे रहा है. देव ने कहा कि देश का विकास, देशवासियों का विकास और छत्तीसगढ़ का विकास डबल इंजन की सरकार में तेजी से होगा. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि आज देश और प्रदेश के एक-एक घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही है. लाभार्थी सम्पर्क अभियान के तहत प्रदेश के सभी स्थानों पर लाभार्थी खुद इन योजनाओं के लाभ गिना रहे थे. देव ने कहा कि तीन महीने में ही भाजपा की प्रदेश सरकार ने अनेक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसले लिए हैं. पाँच साल तक छत्तीसगढ़ में झूठी, मक्कार, अत्याचारी, दुराचारी कांग्रेस की सरकार थी, उससे प्रदेश की जनता ने ऊबकर भाजपा को भरपूर प्रेम दिया, समर्थन देकर कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया. तीन महीने में प्रदेश की भाजपा सरकार अपने किए हुए वादे तेजी से पूरे करके जन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरी है.

उन्होंने कहा, प्रदेश में आज कोई व्यक्ति, परिवार, वर्ग और समाज नहीं मिलेगा जिन्हें भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो. देव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ कांग्रेस की पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने पहुँचने नहीं दिया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने पहली ही कैबिनेट में पाँच महत्वपूर्ण फैसले लिए. इन पाँच महत्वपूर्ण फैसलों की गूंज छत्तीसगढ़ के घर-घर तक, कोने-कोने तक पहुँचनी चाहिए और यह काम हमारे कार्यकर्ता मनोयोग से करें.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति करती है. देश का वैभव, देश का सम्मान देशवासियों का सम्मान पूरे विश्व में प्रदेश की जनता-जनार्दन देख रही है. प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा ने यह साबित किया कि भाजपा जो कहती है, वह करके दिखाती है. देव ने कटाक्ष किया कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो बोलते ही नहीं थे क्योंकि रिमोट कंट्रोल से चलते थे. देव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि यह अवसर है, आप सब प्रण कर लीजिए. जब तीन महीने में मोदी की गारंटी की योजनाएँ पूरी हो सकती हैं, तो अभी तो पाँच साल बचे हैं।

इसलिए जरूरी यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास और लक्ष्य के अनुरूप प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेंट करने के लिए हम सब संकल्पित हों.

भारी संख्या में उपस्थित रहे भाजपा नेता

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा, अजजा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य विद्या सिदार, लोकसभा सह प्रभारी गुरपाल सिंह भल्ला, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, लोकसभा के सह संयोजक खिलावन साहू, पूर्व सांसद कमला पाटले, अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू, पूर्व मंत्री मेघाराम साहू, जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा, महामंत्री द्वय टिकेश्वर गबेल व घनश्याम साहू, प्रीतम गबेल, रामावतार अग्रवाल समेत सभी चारों मंडल इकाइयों के भारी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित थे.

संजय, अग्रवाल, कमलेश ने भी कार्यकर्ताओं में भरा जोश

भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार बनाने का संकल्प लेना है. आज प्रदेश से लेकर देश तक कोई भाजपा के सामने कोई भी राजनीतिक दल खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है. सक्ती, जांजगीर, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यह विश्वास पैदा हुआ है कि हम कौन-से दल के साथ काम करें. मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक और एक ग्यारह का नारा दिया है. हम केंद्र में भाजपा की सरकार बनाएंगे, यह हमारा आत्मविश्वास है, गुरूर नहीं है.

भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े ने कहा कि ये चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का चुनाव है, राष्ट्रहित का चुनाव है, जो देश की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाले हैं. हम सबका यह दायित्व है कि फिर से हमें नरेन्द्र मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व लोकसभा प्रभारी गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया करना है और छत्तीसगढ़ लोकसभा की सभी 11 सीटें मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जीत कर देना है. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि जांजगीर-चांपा की लोकसभा सीट से कमलेश जांगड़े को रिकार्ड मतों से जिताकर भेजेंगे.

हजारों की संख्या में विभिन्न दलों के नेता भाजपा में हुए शामिल

सम्मेलन में सक्ती राजघराने के राजा धर्मेंद्र बहादुर सिंह, जनपद अध्यक्ष राजेश राठौर, जनपद सभापति व गोंडनाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र चौहान, बाराद्वार के पार्षद अजयसिंह राजपूत, युवक कांग्रेस जिला सचिव दीपक राय, सरपंच जायसवाल जोगी कांग्रेस के नरेश अग्रवाल, चरौदा के सरपंच बसंत गबेल सहित हजारों की संख्या में विभिन्न दलों के नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ ही जिला अध्यक्ष ने सबको भाजपा का दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई और स्वागत किया. देव ने कहा कि भाजपा परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है.

भाजपा सरकार जन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही : चौधरी

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पाँच साल के कांग्रेस शासनकाल में तरह-तरह से छत्तीसगढ़ महतारी को अपमानित किया गया, इसे प्रदेश को याद रखना चाहिए. जंगलराज, माफिया राज चलाकर छत्तीसगढ़ को लूटने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, यह बात हमें नहीं भूलनी है. आज छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है और मात्र तीन महीने के कार्यकाल में भाजपा की प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है.

चौधरी ने कहा कि 14 दिसंबर को प्रदेश की भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रमं आवास को स्वीकृति दी गई। 25 दिसंबर को दो साल के बकाया बोनस का भुगतान किया गया. धान खरीदी की लिमिट बढ़ाकर प्रति एकड़ 21 क्विंटल की गई। किए गए वादे के मुताबिक श्री रामलला दर्शन के लिए ट्रेन रवाना की गई. युवाओं के न्याय दिलाने पीएससी की जाँच सीबीआई को सौंपी गई. प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रु. की राशि अंतरित की गई। प्रदेश के किसानों को 13,570 करोड़ रु. की अंतर की राशि एकमुश्त उनके खाते में ट्रांसफर की गई. अस्थायी, संविदा व अन्य कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु कमेटी का गठन किया गया.

चौधरी ने कहा, मोदी गारंटी के अनुसार राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4 प्रतिशत की महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वध्दि करने का निर्णय लिया गया. इस निर्णय से कर्मचारियों को कुल 816 करोड़ रुपए लाभ प्राप्त हुआ. कांग्रेस शासनकाल में पत्रकारों के साथ हुए उत्पीड़न की जांच हेतु गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाये जाने की घोषणा की. मोदी की गारंटी के अनुरुप तेंदूपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 5500 रुपए की गई एवं इसके अतिरिक्त संग्राहकों को 4500 रुपए बोनस की भी घोषणा की गई. चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सक्ती को जिला का दर्जा तो दिया, पर अधोसंरचना पर उसने कोई काम नहीं किया. भाजपा की प्रदेश सरकार अपने शासनकाल में सक्ती को जिले के तौर पर सर्वसुविधासम्पन्न बनाएगी. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश का विश्व मंच पर मान-सम्मान बढ़ा है. देश-दुनिया में उनकी लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है.

मेरी बात ✍ गिरीश पंकज

पुलिस का मानवीकरण हो

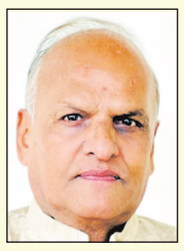

दिल्ली से दो दिन डॉ. वैदिक भाषा साहित्य सम्मान लेकर रायपुर पहुंचा और एयरपोर्ट से सीधे महासमुंद के लिए प्रस्थान किया, जहाँ मुझे दो जुझारू वीरों का सम्मान करना था । यह आयोजन एक तीसरे जुझारू व्यक्तित्व डॉ विमल चोपड़ा ने आयोजित किया था। आप पूर्व निर्दलीय विधायक भी है। पेशे से बड़े नामी चिकित्सक ल। उन्होंने जब मुझसे कहा कि आपको कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आना है तो अपने आप को रोक नहीं सका। थकान के बावजूद वहाँ पहुँचा। मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ,जो अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं। डॉ चोपड़ा भी वर्षों से यही करते रहे हैं। वे खुद अन्याय का विरोध करते हुए पुलिस अत्याचार के शिकार हुए हैं। उनके लिए मैं कलम चलता रहा हूँ। जिन दो वीरों का सम्मान होना था, उनमें एक राजेश चौधरी हैं, जिसने चार लोगों की हत्या के पांच आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाया । पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों की बहुत ही घिनौने तरीके से हत्या की गई थी। अपराधी अब आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं । यह भयंकर नृशंस हत्याकांड कुछ वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें पुलिस ने सिर्फ एक व्यक्ति को आरोपी बनाकर मामले की फाइल बंद कर दी थी। लेकिन राजेश ने कहा, इसमें और भी लोग शामिल हैं। राजेश लगे रहे । आंदोलन करते रहे। पूरा परिवार उनके साथ था । इस बीच पुलिस के एक अधिकारी ने, पुलिस वालों ने तरह-तरह से प्रताड़ित भी किया लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी और अंततः कोर्ट ने हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई। दूसरे वीर अरविंद मिश्रा हैं,जो सागौन प्लांट के जनक कहे जाने वाले मनीराम के परिवार को दस एकड़ जमीन दिलवाने की लड़ाई वर्षों से लड़ रहे हैं। मनीराम जी के नाम पर हरिहर छत्तीसगढ़ मनीराम सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनके परिजनों को सरकार द्वारा वादा करने के बावजूद अब तक दस एकड़ जमीन नहीं दी गई, जिसकी लड़ाई अरविंद मिश्र लगातार लड़ रहे हैं। ऐसे दो लोग का सम्मान की परिकल्पना विमल चोपड़ा ने की तो मैं भला कैसे इंकार कर सकता था। महासमुंद के स्वाध्याय मंडल में सैकड़ो लोगों की उपस्थिति में दोनों का सम्मान हुआ। राजेश चौधरी की बातें सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। बोलते वक्त गला रुँध गया। कुछ समय मुझे रुकना पड़ा। पुलिस के लोग कितने निर्मम हो सकते हैं, इसका पता एक बार फिर राजेश चौधरी की बातों से लगा। जिस परिवार के लोगों की हत्याएँ हुई, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए एक व्यक्ति लड़ रहा है लेकिन उसे तरह-तरह से हतोत्साहित किया जाता रहा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसलिए मैंने अपने भाषण में अंत में कहा कि भारतीय पुलिस के डीएनए में अभी भी अंग्रेजों का खून बह रहा है। जब तक इसकी धमनियों में भारतीयता का, लोकतंत्र का ,करुणा का खून नहीं बहेगा, तब तक पुलिस में सुधार संभव नहीं है। राजनीति और प्रशासन के अमानवीय चरित्र पर मैंने जमकर पीड़ा व्यक्ति। हम और कुछ कर भी नहीं सकते। दुर्भाग्य से सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जो बदलना चाहिए। भारतीय पुलिस का जब तक मानवीकरण नहीं होगा, उसमें लोकतंत्र का करुणा का रक्त प्रवाह नहीं होगा, पुलिस के अत्याचार लगातार जारी रहेंगे। मैं यह देख कर भी चकित हो जाता हूँ कि हमारी सत्ता कैसे विवेक शून्य हो जाती है । जिस पुलिस अफसर प्रताड़ना का आरोप लगाया जाता है, उसे ही बाद में अच्छे पद पर बिठा दिया जाता है। क्यों? पुलिस अफसर की बर्बरता सिद्ध होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती

छत्तीसगढ़/राजधानी समाचार

मनरेगा की मजदूरी प्रतिदिन 400 रु देने की कांग्रेस की गारंटी

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा की कांग्रेस कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन 400रु की मजदूरी दिया जाएगा। वर्तमान में मनरेगा में काम करने वाले को लगभग 200 रु प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। जो कांग्रेस सरकार बनने पर बढ़कर दोगुनी यानी 400 रु प्रतिदिन हो जाएगी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान हुई थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत डेढ़ सौ दिनों तक रोजगार देने के संकल्प को पूरा किया था और कोविड काल के दौरान 27 करोड़ से अधिक श्रम दिवस देकर राष्ट्रीय स्तर पर किर्तिमान स्थापित किया था। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा श्रम की सम्मान की है और श्रमिकों के भलाई के लिए काम किया है। मोदी सरकार ने जो श्रम विरोधी कानून लाया है उसकी समीक्षा की जाएगी और श्रमिकों के हित में सुधार किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन प्रतिदिन 400रु की गारंटी होगी, शहरी रोजगार गारंटी, श्रमिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा इसमें मुफ्त में जांच इलाज और दवा की व्यवस्था रहेगी।

बृजमोहन ने माना महादेव एप बंद करना जरूरी नही

रायपुर। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का यह कहना कि महादेव एप बंद करना जरूरी नही, भाजपा और महादेव एप के सांठगांठ को उजगार करता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान से यह साफ हो गया भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्लू में एफआईआर इसलिये दर्ज की गयी थी कि उन्होंने महादेव सट्टा एप के खिलाफ पूरे प्रदेश में कार्यवाही कराया था, महादेव सट्टा एप को बंद करने के लिये उन्होंने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा था, इससे भाजपा को पीड़ा हो रही थी। आज बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात को स्वीकार किया था एप को बंद करना आवश्यक नही है उसमें जो गलत काम कर रहे है उसके ऊपर कार्यवाही हो। इसका मतलब यह है कि महादेव सट्टा एप को जो हमारा आरोप था भाजपा, केन्द्र सरकार का सरंक्षण है वह साबित होता है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केन्द्र के संरक्षण से महादेव सट्टा एप चल रहा है। प्रदेश में और केन्द्र में भाजपा की सरकार है। डबल इंजन की सरकार है। सरकार को तीन से चार महीने हो गये क्यो बंद नही किया जा रहा है। क्यो रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर और शुभम सोनी को गिरफ्तार करके हिन्दुस्तान नही लाया जा रहा है।

ईडी-भाजपा ने मिलकर भूपेश की छवि खराब करने षड्यंत्र किया

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी के पत्र के आधार पर ईओडब्लू के द्वारा लिखी गई एफआईआर पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा ईडी की जांच और ईओडब्लू के एफआईआर में राजनैतिक षडयंत्र साफ दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले ही यह एफआईआर क्यों दर्ज की गई? ईडी की सारी कार्यवाहियों की टाइमिंग भाजपा के राजनैतिक लाभ पहुंचाने वाली ही क्यों होती है? **ईओडब्लू बताये**- केन्द्र सरकार महादेव ऐप पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही? पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज किये गये एफआईआर का आधार क्या है? जिस असीम दास से ईडी ने रुपये बरामद किया था उसके पास रुपये कहां से आया? ईडी ने उसकी जांच क्यों नहीं किया। असीम दास की फोटो भाजपा नेताओं के साथ आई है तो ईडी ईओडब्लू ने उन दोनो का नाम एफआईआर में क्यों दर्ज नहीं किया। शुभम सोनी की विडियो बाईट भाजपा ने जारी किया था। शुभम सोनी के भाजपा से क्या संबंध है। ईडी ने इसकी जांच क्यों नहीं किया? सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के फोटो भाजपा नेताओं के साथ भी सार्वजनिक है उन दोनो में पूछताछ क्यों नहीं की गई? शुभम सोनी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल को ईडी गिरफ्तार कर के दुबई से वापस क्यों नहीं ला रही है?

भरे मंच में बघेल के सामने सुरेंद्र दाऊ ने निकाली भड़ास

राजनांदगांव. लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. सभी दल के नेता चुनावी प्रचार-प्रसार में जुट गए हैं. इस दौरान पूर्व सीएम और लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल राजनांदगांव चुनावी दौरे पर पहुंचे. जहां उनके पार्टी के नेता ने भरे मंच से ही अपनी भड़ास निकाली. ये तक कहने से उन्होंने गुरेज नहीं किया कि मेरी बाते यदि बुरी लगी हो तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दें. बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ ने मंच से अपनी भड़ास निकालते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सामने कहा, पांच साल में कार्यकर्ताओं का काम और सम्मान नहीं हुआ. पांच साल एक ही नेता दिखा, आज वह गायब हो गया. पांच साल हम आपसे मिलने के लिए तरस गए.

तेलुगु समाज ने डीआरएम पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

रायपुर। तेलुगु समाज के प्रतिनिधियों के साथ डीआरएम की ओर से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है. समाज ने आरोप लगाया है कि आंध्र-तेलुगु समाज का प्रतिनिधिमंडल आज डीआरएम संजीव कुमार से वन्दे भारत ट्रेन के संबंध में ज्ञापन देने पहुंचा था. वहां डीआरएम ने प्रतिनिधिमंडल से दुर्व्यवहार किया. उन्होंने प्रतिनिधियों से बदतमीजी करते हुए कहा कि आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? डीआरएम के इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से आहत तेलुगु समाज के प्रतिनिधिमंडल ने निर्णय लिया है कि इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से करेंगे. प्रतिनिधिमंडल में आंध्र एसोसिएशन, तेलुगु वेलफेयर सोसायटी, छत्तीसगढ़ रेड्डी संघम, आंध्र ब्राह्मण समाज, छत्तीसगढ़ तेलुगु अभ्युदय ब्राह्मण समाज, छत्तीसगढ़ तेलुगु समाज, छत्तीसगढ़ शिष्टकरनम एसोसिएशन सहित अनेक संगठनों के सदस्य शामिल थे. विदित हो कि छत्तीसगढ़ में तेलुगु समाज के लगभग 15 लाख से अधिक की जनसंख्या है.

निर्वाचन कार्य ड्यूटी पर लगे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए उपयुक्त सुविधा का रखे ध्यान

कलेक्टर सिंह ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने आज सेजबहार स्थित शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सेजबहार रायपुर और बीटीआई मैदान शंकर नगर स्थित शासकीय स्कूल में लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने चुनाव सामग्री के वितरण के लिए बनाई गई व्यवस्था का अवलोकन किया। कलेक्टर ने कहा कि पोस्टल बैलेट के संबंध में सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। जिन अधिकारियों कर्मचारियों को डाक मतपत्र दिया जाना है, उनकी अंतिम सूची बना ली जाए और समय सीमा के भीतर वितरण किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सेकंड रेंडमाइजेशन, कमिसनिंग, डाक मतपत्रों के वितरण और वोटर स्लीप के संबंध में टाइम टेबल बना कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। डॉ सिंह ने कहा कि जहां मतगणना होनी है वहीं पर ईवीएम की कमिशनिंग भी की जानी है। इस संबंध में उपयुक्त इंतजाम किए जाएं। पुलिस विभाग सुरक्षा के साथ-साथ सेजबहार के रास्ते यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करें। यथास्थान सीसीटीव्ही भी लगाएं। जिन अधिकारियों कर्मचारियों को

डाक मतपत्र दिया जाना है, उनकी अंतिम सूची बना ली जाए और समय सीमा के भीतर वितरण किया जाए। उनके लिए शुद्ध पेयजल एवं महिला पुरुष के लिए पृथक पृथक शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित कर लिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि यह ध्यान रखें कि ड्यूटी में आए कर्मचारियों को यथासंभव सुविधा मिले एवं कोई तकलीफ ना हो। पोस्टल बैलेट के संबंध में सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। एसपी श्री संतोष सिंह ने कहा कि स्ट्रांग रूम में तीन स्तर की बेरिकेंडिग की जानी है यह अच्छी तरीके से की जाए ताकि निर्वाचन कार्य सुचारु सरूप से सम्पन्न हो। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को कहा। साथ ही सामाग्री वितरण सहित अन्य निर्वाचन कार्य के समय स्ट्रांग रूम के आसपास के मार्गों में यातायात सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि बलौदाबाज़ार विधानसभा के लिए सामग्री वितरण केंद्र सत्यनारायण अग्रवाल शासकीय महाविद्यालय तिल्दा और धरसींवा विधानसभा क्रमांक 47, रायपुर नगर पश्चिम विधानसभा क्रमांक 49, रायपुर उत्तर विधानसभा क्रमांक 50 को सामग्री वितरण बी टी आई शंकर नगर से किया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचरण संहिता और निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक यह प्रभावशील रहेगी। राज्य में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भी सतत अद्यतीकरण में मतदाताओं के नाम जोड़े जाने की कार्यवाही निरंतर प्रक्रियाधीन है।

राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे- रैंप, पेयजल, विद्युत प्रकाश, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। प्रत्येक मतदान केन्द्र में मतदाता सहायता केन्द्र का निर्माण किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि सभी मतदान केन्द्रों में बुजुर्गजनों एवं दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु मतदाता मित्र आवश्यक सहयोग हेतु उपस्थित रहेंगे।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.